बिहार सरकार
वित्त विभाग

हरित बजट

2024-25

बिहार सरकार

हरित बजट

2024-25

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

भारत की अध्यक्षता में हाल ही में जी-20 की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक के थीम ''एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य'' के तहत भारत की प्राथमिकताएं समावेशी विकास के साथ जलवायु, वित्तीय प्रबंधन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं।[1] पेरिस समझौता, आइची जैव-विविधता लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय बचनबद्धताएं निम्न कार्बन वाले भविष्य की दिशा में दुनिया के सामूहिक प्रयास की महत्वपूर्ण जरूरत को रेखांकित करती हैं। जलवायु सुधार से पूरे विश्व को लाभ पहुँचता है परंतु जलवायु सुधार पर होनेवाले व्यय का भार स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि यह वंचित (वल्नरेबल) समुदाय जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का सामना करते हैं। इस संबंध में भारत जैसे विकासशील देश में राज्यों के स्तर पर भी जलवायु और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण ''हरित बजट'' की भूमिका को नीति-निर्माण हेतु व्यवहार में लाया जा रहा है।

बिहार 2020-21 में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था, जिसका फोकस पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं को विकासमूलक रखते हुए अपने बजट को हरित योजनाओं के लिए टैगिंग करना था। बिहार जैसे राज्य के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यह राज्य बाढ़, सूखा, भूकंप, आंधी-तूफान, बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों के लिहाज से अतिसंवेदनशील है। हरित बजट निर्माण से वस्तुत: अपने संसाधनों, परिव्ययों और नीतियों पर नजर रखने में मदद मिलती है, समन्वित कार्रवाई को बल मिलता है, भावी जरूरतों के वित्त-पोषण का अनुमान हो पाता है और संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है। हरित बजट के माध्यम से सरकारें हरित निवेश को प्राथमिकता दे सकती हैं, राज्य की प्रगति पर नजर रख सकती हैं, और विभिन्न बजट चक्रों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समेकित कर पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताओं के साथ राजकोषीय संरेखण सुनिश्चित कर सकती हैं।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने तथा वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जल-जीवन-हरियाली-अभियान (जेजेएचए) जैसे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी) जलवायु संबंधी अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए रोडमैप उपलब्ध कराकर हरित बजट निर्माण के प्रयासों के तहत काम कर रहा है।[2] वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए राज्य की ऊर्जा, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, परिवहन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंदित कर 'जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ' विकसित करने की भी योजना है।[3] राज्य ने वायु प्रदूषण के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए शहरी क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रखंड स्तर पर इसकी शुरुआत कर दी है।

---

1 नीति आयोग. ''ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा''. 2023. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-12/REVISED_Report-on-G20-Conference-on-Green-Growth_FINAL-REVISED.pdf

2 बिहार सरकार. 2015. ''राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना''.

3 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

इस प्रकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिहार के हरित बजट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना पर्यावरण संबंधी चिंताओं को राज्य सरकार के वार्षिक व्यय में समाहित करने की दिशा में पहल है। इस अभ्यास के जरिए उन कार्यक्रमों और नीतियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित रहा है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता के लिए योगदान करते हैं। समय के साथ हरित पहलों को सतत विकास लक्ष्यों के लिहाज से सूचीबद्ध करने से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए संसाधनों का आवंटन, सरकारी विभागों के बीच समन्वय, हितधारकों का सशक्तीकरण और भविष्य की दिशा में प्रगति हेतु नीतिगत लक्ष्यों को वित्तीय योजनाओं में बदलने में मदद मिलेगी।

विषय वस्तु

आमुख		i-ii
शब्द संक्षेप		v-vi
1.	परिचय	01
2.	बिहार का पर्यावरण : एक अवलोकन	02
3.	बिहार में हरित बजट निर्माण	10
4.	बिहार में हरित बजट : सारांश	15
5.	राज्य में मुख्य हरित पहलें	23
6.	संदर्भ सूची	82

तालिका सूची

तालिका 1: बिहार और संपूर्ण भारत में पर्यावरण की स्थिति 04

तालिका 2: हरित बजट के संबंध में दृष्टिकोण 12

तालिका 3: बिहार में हरित बजट सारांश 17

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरित बजट विभाग-वार विवरणी 18

तालिका 5: बिहार में हरित बजट का विभाग-वार विवरण 19

तालिका 6: हरित बजट के लिए चिन्हित कुल योजनाएँ 20

तालिका 7: बिहार में हरित बजट का प्रदर्शन (2024-25) 20

तालिका 8: विभागवार एस0डी0जी0 मैपिंग 21

चित्र सूची

चित्र 1: बिहार में हरित बजट निर्माण की रूपरेखा 10

चित्र 2: हरित बजट निर्माण के थीम संबंधी पहलू 11

चित्र 3: हरित घटक और पर्यावरणीय स्थायित्व का महत्व 13

चित्र 4: विभागवार एसडीजी वितरण 22

चित्र 5: विभागवार गतिविधि वितरण 22

अनुसूची

अनुसूची 1: विभागवार हरित बजट विवरण 42-81

शब्द संक्षेप

एजीबी	भूम्योपरि जैव-भार
एएमआरयूटी (अमृत)	अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन
बीसीएम	अरब घनमीटर
बीजीबी	अधोभूमि जैव-भार
बीएमएसआइसीएल	बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसपीसीबी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बीएसआरडीसीएल	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बीडब्ल्यूडीएस	बिहार जलसंभर क्षेत्र विकास समिति
सीएएक्यूएमएस	सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र
सीएएमपीए (कैंपा)	क्षतिपूर्ति-परक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएमसी	व्यापक अनुरक्षण नीति
सीएनजी	दाबित प्राकृतिक गैस
जीएआइएल (गैल)	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
जीसीसी	सकल व्यय संविदा
जीआइएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआरआइएचए (गृहा)	समेकित पर्यावास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आइएमडी	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग
आइएसआरओ (इसरो)	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
जेजेएचए	जल-जीवन-हरियाली अभियान

केडब्ल्यूएच	किलोवाट आवर
एलआइएसएस (लिस्स)	लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर
एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएलडी	दस लाख लीटर प्रतिदिन
एमआरएफ	सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधा
एमडब्ल्यूपी	मेगावाट पीक
एनएपीसीसी	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
एनबीएसएपी	राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना
एनओ2	नाइट्रोजन डायॉक्साइड
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्त
पीएम10	10 माइक्रोमीटर या कम व्यास वाले कणीय पदार्थ
पीएम2.5	2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास वाले महीन कणीय पदार्थ
पीएमसी	पटना नगर निगम
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
सएपीसीसी	राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसडीजी	सुस्थिर विकास लक्ष्य
एसओसी	मृदा जैव कार्बन
एसआरआइ (श्री)	चावल सघनीकरण प्रणाली
टीपीडी	टन प्रतिदिन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
डब्ल्यूपीयू	अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई

1. परिचय

हाल के वर्षो में समाज पर प्रभाव डालने वाले कार्बन उत्सर्जन, जैव-विविधता में ह्रास और पर्यावरण क्षरण के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्रवाई आवश्यक है। जलवायु संबंधी वैश्विक प्रतिबद्धता और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की भी दीर्घकालिक योजना है, जो स्थिर और न्याय के साथ विकास की दिशा में हरित ऊर्जा, इसके दायित्वपूर्ण उपयोग एवं पर्यावरण की स्थिरता पर बल देने वाली है। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट- 2022 में भारत की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रेखांकित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2070 तक निवल-शून्य (नेट-ज़ीरो) उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा पर 50 प्रतिशत निर्भरता तथा 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत कमी शामिल हैं।[4] आर्थिक प्रगति को बरकरार रखते हुए पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर समेत विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में ही हरित बजट निर्माण को अपनाकर बिहार ने देश में अग्रणी भूमिका निभायी है। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर 10.6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करके बिहार देश के सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है।[5] हालांकि इससे संसाधनों की खपत, प्रदूषण, निर्वनीकरण और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि समेत अनेक पर्यावरण संबंधी जोखिम पैदा होते हैं, जो पारिस्थितिकीय तत्रों (इकोसिस्टम) पर दबाव डाल सकते हैं, प्रजातियों को संकटग्रस्त कर सकते हैं और मौसम की स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। कृषि, मत्स्य और पर्यटन जैसे क्षेत्र बिहार की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, बाढ़ और सूखा से राज्य के पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता, जीवन और जीविका को खतरा पैदा होता है जो इन्हें खास तौर पर असुरक्षित क्षेत्र बना देता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे प्राथमिकता के आधार पर जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा समुदाय की प्रतिरोध-क्षमता में निवेश करके राज्य द्वारा अपनी जनता और पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

बिहार की उपजाऊ भूमि और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में विकास की असीम संभावनायें है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वन आवरण में वृद्धि करने और जल संरक्षण से लेकर समुदायों की सहभागिता बढ़ाने तक अनेक जलवायु संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। हरित बजट अभ्यास ने जलवायु संबंधी चिंताओं को बजट निर्माण के साथ एकीकृत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, तथा विभागों के लिए नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए रोडमैप उपलब्ध करा दिया है।

---

4 जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022. https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2022

5 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

2. बिहार का पर्यावरण : एक अवलोकन

बिहार, भारत के पूर्वी भाग में $24^{0}20'10''$ से $27^{0}\ 31'15''$ उत्तरी अक्षांश और $82^{0}\ 19'50''$ से $88^{0}17'40''$ पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। राज्य की समुद्रतल से औसत ऊंचाई लगभग 52.73 मीटर है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड अवस्थित हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9 प्रतिशत है। वहीं, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या लगभग 10.40 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।[6]

राज्य में वर्षापात चार मौसमों में विभक्त है – दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून (जून से सितंबर), शीतकालीन वर्षा (दिसंबर से फरवरी), ग्रीष्मकालीन वर्षा (मार्च से मई) और उत्तर-पश्चिमी मॉनसून (अक्तूबर-नवंबर)। वर्ष 2022-23 में बिहार में 849.1 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षापात हुआ जिसमें दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून का 81.7 प्रतिशत हिस्सा था। [7]राज्य की उपोष्ण जलवायु की विशेषता गर्म और नम ग्रीष्म ऋतु, हल्की ठंड वाली शीत ऋतु तथा मॉनसून वाली वर्षा ऋतु हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में औसत वार्षिक भूतल वायु तापमान 24.7^{0} सेल्सियस, औसत न्यूनतम तापमान 7.1^{0} सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 42.3^{0} सेल्सियस है। [8]

बिहार का भूगोल विविधतापूर्ण है। इसके तीन मुख्य क्षेत्र हैं : उत्तर में हिमालय की तराई, मध्य में कृषि योग्य मैदानी भाग और दक्षिण में खनिज संसाधनों से संपन्न पठार। गंगा के मैदान को उत्तरी और दक्षिणी – दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग चौरस और बाढ़-प्रवण क्षेत्र है, जबकि दक्षिण बिहार पहाड़ियों और पठारों वाला है। मैदानी भागों की मिट्टी मुख्यतः दोमट, बलुआही, या बलुई-दोमट है। बिहार का हिमालय से लेकर गंगा के मैदान तक का विस्तृत भाग विविधतापूर्ण पारिस्थितिकीय और जैव-विविधता से भरा हुआ है। राज्य में 2.25 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आस-पास आर्द्र भूमि है। यह बात राज्य में उनके पारिस्थितिकीय महत्व को रेखांकित करता है।[9]

राज्य में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य और रजौली वन्यजीव अभयारण्य जैसे वन्यजीव अभयारण्य, तथा कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य, बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य और कांवर झील पक्षी अभयारण्य जैसे पक्षी अभयारण्य, बाघ अभयारण्य (वाल्मीकि बाघ आरक्ष), डॉल्फीन (सूंस) अभयारण्य

6 भारत की जनगणना. 2011. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. http://www.censusindia.gov.in/.

7 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

8 मौसमविज्ञान केंद्र, पटना.

9 भारतीय नमभूमियों का अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण. 2021. स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद, भारत https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

(विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य), और संरक्षण तथा सामुदायिक आरक्ष (गोगाबिल संरक्षण आरक्ष, गोगाबिल सामुदायिक आरक्ष तथा भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष) मौजूद हैं। [10]

वर्ष 2021 के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 9722 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन (फॉरेस्ट कवर) है जिसमें एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्राकृतिक वन और वैधिक रूप से निरपेक्ष 10 प्रतिशत या अधिक सघनता (क्राउन डेंसिटी) वाले वृक्षाच्छादन (ट्री कवर) शामिल हैं। [11]वहीं, उच्च रिजोल्यूशन वाली उपग्रहीय प्रतिबिंब (लिस-IV, 5.8 मी.) पर आधारित भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार राज्य में व्यापक वनाच्छादन 13,896 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भूक्षेत्र का 14.75 प्रतिशत है। [12]अनुमानित वनाच्छादन में वन क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित वृक्षाच्छादन शामिल हैं। इसमें मुख्यत: दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बांका और मुंगेर जिलों में और उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण में अवस्थित शुष्क पर्णपाती साल वन और आर्द्र पर्णपाती साल वन शामिल हैं। वर्ष 2021 में मुख्यत: मिट्टी और पेड़-पौधों के मृत भागों में 568.8 लाख टन वन्य कार्बन मौजूद था। इसमें सर्वाधिक हिस्सा मृदा जैव कार्बन (एसओसी) का था, जो 2021 में बिहार के कुल वन्य कार्बन पूंज (पूल) का 63.1 प्रतिशत था।[13]

बिहार को गंगा और उसकी सहायक नदियों यथा- गंडक, कोशी तथा महानंदा आदि नदियों का वरदान प्राप्त है। इन नदियों से सिंचाई, पेयजल, नौकायन और मात्स्यिकी के लिए जल उपलब्ध होता है। नहरों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए नदियों के पानी का सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही, राज्य के अधिकांश भाग में मौजूद उर्वर गांगेय जलोढ़ मिट्टी के कारण राज्य में प्रचुर भूजल संसाधन भी मौजूद है। वर्ष 2023 में राज्य में कुल 33.96 अरब घनमीटर का वार्षिक भूजल संभरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) हुआ था जिसका 44.7 प्रतिशत हिस्सा निकाला गया था। [14] अपनी भौगोलिक स्थिति और जल-मौसम वैज्ञानिक प्रणाली की अस्थिरता के कारण राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है और हाल के दशकों में इन आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ते हुए दिखी है। उत्तर बिहार के जिले बाढ़ के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील हैं और अचानक आनेवाली बाढ़, नदियों से होनेवाले बाढ़ तथा जल-जमावों के कारण कृषि भूमि, संपत्ति, जन-जीवन और बुनियादी संरचनाओं को काफी क्षति पहुंचती है।

राज्य में वायु प्रदूषण मुख्यत: सड़कों की धूल, कृषि, जीवाश्म इंधन जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से उत्सर्जन के कारण होता है। शहरी क्षेत्र खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्योंकि संकेंद्रित प्रदूषक ताप संचित करके धुंध पैदा करते हैं। वर्ष 2022-23 में पटना की वायु गुणवत्ता, खास कर लघु कणीय पदार्थों (पीएम2.5), वृहत कणीय पदार्थों (पीएम10) और

---

10 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

11 ''स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021''. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

12 ''चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28)''. 2023. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

13 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

14 ''नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया''. 2023. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf

नाइट्रोजन डायक्साइड के मामले में, राष्ट्रीय मानकों से बेहतर थी। [15]वर्ष 2021 में राज्य के लगभग 13 जिले फ्लोराइड से, 10 जिले नाइट्रेट से, 22 जिले आर्सेनिक से, और 19 जिले आयरन से प्रदूषित थे जहां ये पेयजलों में नियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक थे। [16] राज्य में निकलने वाले मलजल की अनुमानित मात्रा 2020 में 2276 एमएलडी प्रतिदिन था। [17]

तालिका 1 : बिहार और संपूर्ण भारत में पर्यावरण की स्थिति

A. बिहार की सामान्य विवरणी [18]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	2011	94163 (2.86%)	3287469 (2.40%)
जनसंख्या (करोड़)	2011	10.41 (8.60%)	121.06 (17.76%)
ग्रामीण जनसंख्या (करोड़)	2011	9.234 (88.71%)	83.375 (68.85%)
शहरी जनसंख्या (करोड़)	2011	1.176 (11.30%)	37.70 (31.14%)
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	2011	1106	382

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

15 सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड. https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/

16 भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय. भारत सरकार. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1707520

17 नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTIyOF8xNjE1MTk2MzIyX21lZGlhcGhvdG85NTY0LnBkZg==

18 जनसंख्या गणना. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. 2011. https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables

B. स्थिरता और जलवायु सूचकांक

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
सतत विकास लक्ष्य (समग्रता में रैंक)[19,20]	2020	28/28 (स्कोर 52)	112/166 (स्कोर 63.4) (2023)
साफ पानी और स्वच्छता (लक्ष्य 6) संबंधी रैंक [18]	2020	91	83
किफायती और स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7) संबंधी रैंक [18]	2020	78	92
भूमि पर जीवन (लक्ष्य 15) संबंधी रैंक [18]	2020	62	66
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (स्कोर)[21]	2021-22	21.0	29.1
राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक (स्कोर)[22]	2021-22	38.3	40.6
पर्यावरण सुस्थिरता (स्कोर) [21]	2021-22	33.7	37.7
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (स्कोर) [23]	2019	37.8	-
जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता (रैंक) [24,25]	2019-20	6/29 (स्कोर 0.614) शीर्ष अति संवेदनशील राज्यों का 25%	7/181 (CRI स्कोर 16.67) वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक

C. भूमि उपयोग पैटर्न [26,27]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कुल अकृष्य भूमि (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	4289.18 (45.83)	165479.08 (50.34)
शुद्ध बुआई क्षेत्र (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	5070.39 (54.17)	141006.77 (42.89)
सकल बुआई क्षेत्र (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	7328.57	219158.36

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

19 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020. https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

20 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023. https://dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2023-india.pdf

21 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अलायंस फॉर ऍन इनर्जी इफिशिएंट इकोनोमी, 2022. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22. https://stateenergyefficiencyindex.in/wp-content/uploads/2023/04/State-Energy-Efficiency-Index-2021-22-Report.pdf

22 नीति आयोग. राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक - चक्र 1. 2022. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRoundI-10-04-2022.pdf

23 नीति आयोग. 2019. संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक. https://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf

24 सामान्य रूपरेखा का उपयोग करके भारत में अनुकूलन योजना निर्माण के लिए जलवायु अरक्षितता मूल्यांकन, 2019-20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग. https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf

25 वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021. संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

26 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

27 भूमि उपयोग सांख्यिकी - एक नजर में (अनंतिम अनुमान). आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार. –Land Use Statistics At a Glance | Official website of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India (desagri.gov.in)

D. वन संसाधन [28]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कुल हरित आवरण (वर्ग किमी) (LISS-IV, 5.8m) [29]	2019	13,896 (14.75)	-
कुल वनाच्छादन (वर्ग किमी)	2021	7381 (7.84)	713789 (21.71)
कुल आच्छादन (वर्ग किमी)	2021	2341 (2.49)	95748 (2.91)
वनों के प्रकार (वर्ग किमी)			
अति सघन वन (VDF)	2021	333 (0.35)	99779 (3.04)
मध्य सघन वन (MDF)	2021	3286 (3.49)	306890 (9.33)
खुले वन (OF)	2021	3762 (4.00)	307120 (9.34)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

E. वनों में कार्बन स्टॉक [27]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
वनों में कार्बन स्टॉक (हजार टन में)	2021	56881 (100.0)	7203846 (100.0)
भूम्योपरि जैव-भार (AGB)	2021	14743 (19.97)	2319910 (32.50)
अधोभूमि जैव-भार (BGB)	2021	5249 (7.11)	718852 (10.07)
मृत काष्ठ	2021	231 (0.31)	47665 (0.67)
कूड़ा-करकट	2021	785 (1.06)	107251 (1.50)
मृदा जैव कार्बन (SOC)	2021	35873 (48.60)	4010168 (56.18)
बढ़ता स्टॉक (लाख घनमीटर में)	2021	715.6	61675.0

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े टन में प्रति हेक्टेयर स्टॉक दर्शाते हैं।

---

27 भूमि उपयोग सांख्यिकी - एक नजर में (अनंतिम अनुमान). आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार. –Land Use Statistics At a Glance | Official website of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India (desagri.gov.in)

28 ''स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (2022)''. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

29 ''चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28)''. 2023. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

F. जलवायु [30]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
औसत वार्षिक तापमान (0 सेल्सियस)	2022	24.7	25.21
औसत न्यूनतम तापमान (0 सेल्सियस)	2022	7.1	19.89
औसत अधिकतम तापमान (0 सेल्सियस)	2022	42.3	30.53
वार्षिक वर्षापात (मिलीमीटर)	2022	849.1	1257.0

G. आर्द्र भूमि [31,32]

सूचक	इकाई	वर्ष	बिहार	भारत
थलीय नमभूमि (प्राकृतिक)				
झील/ तालाब	संख्या	2021	387	11740
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		14820	729532
गोखुर झील/ कट-ऑफ मीएंडर (घुमावदार कटाव)	संख्या	2021	912	4673
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		16432	104124
उच्च अल्टीट्यूड (तुंगता)	संख्या	2021	-	2707
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		-	124253
नदी तटीय नमभूमि	संख्या	2021	172	2834
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		2194	91682
जल जमाव-ग्रस्त	संख्या	2021	1537	11957
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		30700	315091
नदी/ धारा	संख्या	2021	209	11747
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		294685	5258385

30 वार्षिक रिपोर्ट 2022. भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, भूमि विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार. https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/ar2022.pdf

31 स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, इसरो. 2021. ''भारतीय नमभूमियों का अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण''. स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

32 राष्ट्रीय नमभूमि सांख्यिकी. भारत में नमभूमियों के क्षेत्रफल का प्रकार आधारित अनुमान. https://indianwetlands.in/wetlands-overview/national-wetlands-statistics/.

सूचक	इकाई	वर्ष	बिहार	भारत
थलीय नमभूमि (मानव निर्मित)				
जलाशय/ बैराज	संख्या	2021	71	14894
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		9116	2481987
तालाब	संख्या	2021	1216	122370
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		6484	1310443
जल जमाव-ग्रस्त	संख्या	2021	22	5488
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		335	135704
लवण कुंड	संख्या	2021	-	60
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		-	13698
कुल थलीय नमभूमि	संख्या	2021	4526	188470
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		374766	10564899

H. भू-जल संसाधन[33]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
वार्षिक भू-जल पुनर्भरण (बिलियन घनमीटर में)	2023	33.96	449.08
निकासी योग्य वार्षिक भू-जल संसाधन (बिलियन घनमीटर में)	2023	30.72	407.21
सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निकासी (बिलियन घनमीटर में)	2023	13.75	241.34
भूजल निकासी का स्तर (%)	2023	44.76	59.26

33 ''नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023''. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी). https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf.

I. वायु प्रदूषण [34]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कणीय पदार्थ 2.5 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	100	60
कणीय पदार्थ 10 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	190	119
सल्फर डायॉक्साइड (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	10	11
नाइट्रोजन डायॉक्साइड (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	42	39

J. भूजल प्रदूषण [35]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
फ्लोराइड (1.5 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	13	370
नाइट्रेट (45 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	10	423
आर्सेनिक (0.01 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	22	152
आयरन (1.0 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	19	341

K. अपशिष्ट प्रबंधन [35]

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
मलजल की निकासी (एम0एल0डी0)	2020	2276	72368
मलजल उपचार क्षमता – स्थापित (एम0एल0डी0)	2020	10	31841
मलजल उपचार क्षमता – प्रस्तावित (एम0एल0डी0)	2020	621	4827

34 सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड. https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/. 4 फरवरी 2024 को प्राप्त.

35 भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय. भारत सरकार. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1707520

36 भारत सरकार. 2021. नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTIyOF8xNjE1MTk2MzIyX21IZGlhcGhvdG85NTY0LnBkZg==

3. बिहार में हरित बजट निर्माण

राज्य सरकार, बिहार विधान मंडल में वर्ष 2020–21 से हरित बजट प्रस्तुत करती रही है। इस प्रकार, बिहार में अपनाई जा रही हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया एक सरल और समावेशी दृष्टिकोण है। राज्य के बजट में पर्यावरण संबंधी आवंटनों और व्ययों को टैग करने में विभिन्न हितधारक विभागों की भूमिका शामिल होती है। हरित बजट निर्माण के इस दृष्टिकोण में तीन मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है : संगठित प्रतिक्रिया, हरित कार्य प्रणाली और नीतिगत मंत्रणा।

सर्वप्रथम, इस रूपरेखा में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, वन, ऊर्जा, जल संसाधन, परिवहन, ग्रामीण एवं शहरी विकास आदि विभिन्न क्षेत्रों में हरित विचारों को मौजूदा बजट आवंटन में शामिल करने के लिए व्यापक और समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए विभागों के बीच समन्वय स्थाापित किया जाता है।

दूसरे, रियोमार्कर पद्धति के उपयोग और सतत विकास लक्ष्यों के साथ मैपिंग करने से वैश्विक मानकों के अनुसार पर्यावरण संबंधी व्ययों का वर्गीकरण और ट्रैकिंग किया जाता है।

तीसरे, नीतिगत मंत्रणा की प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के साथ राज्य की नीतियों का सरेखण शामिल होता है। कुल मिलाकर, राज्य में हरित बजट निर्माण की प्रारंभिक रूपरेखा को पर्यावरण संबंधी इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करके पर्यावरण संबंधी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया गया है।

चित्र 1: बिहार में हरित बजट निर्माण की रूपरेखा

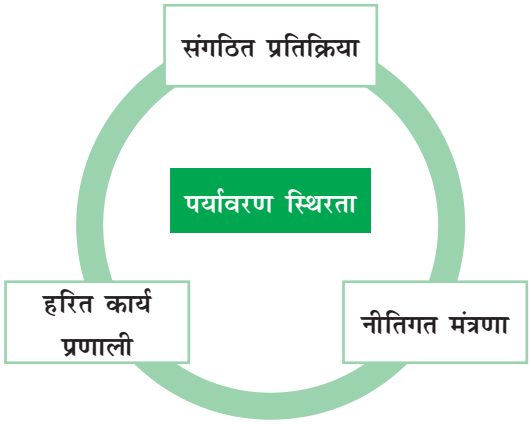

हरित बजट निर्माण में थीम संबंधी अनेक पहलू शामिल होते हैं, जिनका लक्ष्य पर्यावरण संबंधी विचारों को सरकारी व्ययों के विभिन्न पहलुओं के साथ समेकित करना होता है। थीम संबंधी विभिन्न पहलुओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण, सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, और सार्वजनिक परिवहन जैसी अवसरचनाओं का निर्माण, जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन और न्यूनीकरण, वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण, अपशिष्ट में कमी, उसका पुनर्चक्रण और उत्तरदायित्व के

साथ निपटान, जमीन का सतत् उपयोग, विलुप्तप्राय प्रजातियों और पर्यावासों की रक्षा, पारिस्थितिकीय तत्रों की पुनर्स्थापना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा, हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण और सबको सतत् आजीविका उपलब्ध कराना शामिल हैं। हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त हरित योजना और अभ्यास की विभिन्न थीमों को चित्र 2 में दर्शाया गया है।

चित्र 2: हरित बजट निर्माण के थीम संबंधी पहलू

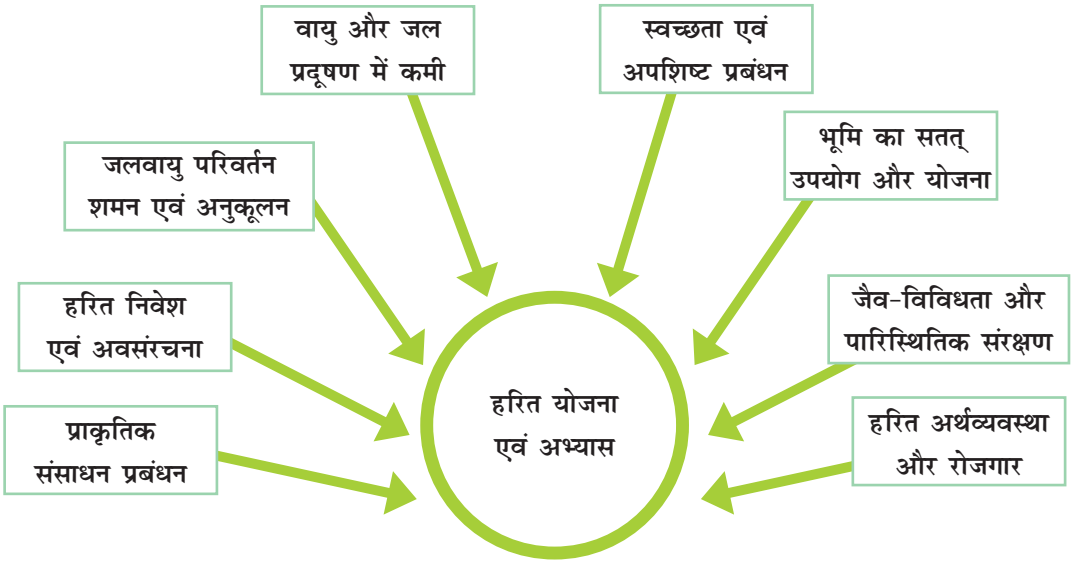

इस प्रकार, हरित बजट निर्माण विभागों के बीच समन्वय को मजबूती और पर्यावरण की सुस्थिरता के लिए संगठित प्रतिक्रिया को बढ़ावा की रणनीति है। इससे नीति-निर्माताओं को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय क्षेत्र के अंदर अपने संसाधनों का मूल्यांकन और पुनर्विन्यास करने में मदद मिलती है। हरित बजट निर्माण अभी भी आरंभिक चरण में है इसलिए क्षेत्रगत परिणामों और उपलब्धियों को व्यक्त करने वाले व्ययों का व्यापक विश्लेषण करने के लिहाज से इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में हरित बजट निर्माण की प्रणाली में शामिल विभिन्न चरणों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- **चरण 1 :** इसमें विभिन्न हितधारक विभागों की मौजूदा वार्षिक योजनाओं और बजटों में विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए संभावित हरित हस्तक्षेपों को समझने के लिए किसी कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देशों और उद्देश्यों की विभिन्न स्रोतों से समीक्षा की जाती है। हरित बजट की संभावना को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संबंधी प्रत्यक्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों और सतत् विकास लक्ष्यों के लिए अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले कार्यक्रमों, दोनो पर विचार किया जाता है।

- **चरण 2 :** विहित प्रपत्र के अनुसार, हितधारक विभागों से संबंधित स्कीमों एवं उनके बजटीय प्रावधानों को एकत्र किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इससे हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में परिशुद्धता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिहाज से बजट की ट्रैकिंग और आंकड़ों का

प्रबंधन व्यवस्थित करने के लिए वित्त विभाग तकनीकी सहयोग देता है और विचार-विमर्श करता है।

- **चरण 3 :** हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के कार्यक्रम स्तर के बजट कोड का उपयोग करते हुए गहन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसका लक्ष्य दोहरी गणना को समाप्त करना और पर्यावरण पर केंद्रित कार्यक्रमों की पहचान करना होता है। साथ ही, ये कोड विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और सतत विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के साथ भी टैग हुए हैं।

तालिका 2: हरित बजट के संबंध में दृष्टिकोण

पद्धति:

बजटीय प्रावधान और व्यय का आकलन	
हरित योजना निर्माण के उद्देश्यों के साथ संरेखित हितधारक विभागों की पहचान	विभागीय उद्देश्यों की उनकी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों के जरिए समीक्षा
	हरित उद्देश्यों के साथ संरेखित विभागीय नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा
हरित योजना निर्माण में योगदान करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की ट्रैकिंग	विस्तृत अनुदान मांगों और बजट दस्तावेजों की समीक्षा
	विभागीय राजकोषीय योजना, उसके लक्ष्यों और उपलब्धियों की ट्रैकिंग के लिए हितधारकों के साथ परामर्श
ट्रैक की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट आवंटनों और व्ययों की टैगिंग	राजकोषीय बजट परिव्यय से बजट प्रावधानों का विभाग-वार और योजना-वार संग्रहण
	विभागीय बजट आवंटन और व्यय से हरित बजट के प्रावधानों का संकलन (कोलेशन)
	टैग की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के हरित गतिविधि संबंधी महत्व की समीक्षा

बिहार में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी बजट आवंटनों को टैग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के टूल रियो-मार्कर पद्धति का उपयोग किया गया। इस विधि में विभिन्न स्कीमों के तहत किए जानेवाले व्यय को पर्यावरण संबंधी प्रभाव के आधार पर पूर्णत: समर्पित, महत्वपूर्ण और सीमांत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रक्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए संबंधित विभाग के बजट शीर्षों का उपयोग करते हुए रियो-मार्कर प्रणाली और सतत विकास लक्ष्य मैपिंग (एसडीजी मैपिंग) को अपनाया जाता है।

हरित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए विहित प्रपत्र तैयार किया गया। इसके बाद विभागों को हर शीर्ष का औचित्य स्पष्ट करते हुए बजट आवंटन निर्धारित किया गया। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की ट्रैकिंग और लेबलिंग के लिए सतत

विकास लक्ष्य सूचीकरण और रियो-मार्कर मानक रूपरेखा का उपयोग किया गया। विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं के वर्गीकरण के लिए हर योजना की उसके लक्ष्यों और घटक अंगों के साथ गहन जांच की गई। विभिन्न घटकों की ट्रैकिंग के जरिए योजनाओं के संचयी प्राप्ताकों (क्यूमुलेटिव स्कोर) की गणना की गई। इस बजट टैगिंग प्रक्रिया को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी), राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (एनबीएसएपी) और हरित गतिविधि वर्गीकरण पर मौजूद दस्तावेजों के साथ जोड़ा गया। योजना-वार स्कोर के आधार पर विभिन्न योजनाओं के बजट शीर्षों के साथ ''हरित'' का टैग लगाया गया।

चित्र 3: हरित घटक और पर्यावरणीय स्थायित्व का महत्व

पूर्णत: समर्पित (90-100 प्रतिशत)	राष्ट्रीय वानीकीकरण कार्यक्रम, बाघ परियोजना, ई-वाहन योजना, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण योजनाएं इत्यादि
अत्यधिक महत्व (75-90 प्रतिशत)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन इत्यादि
अधिक महत्व (50-75 प्रतिशत)	परंपरागत कृषि विकास योजना, जलवायु अनुकूल कृषि योजना, भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन, राष्ट्रीय भू-जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम इत्यादि
मध्यम महत्व (25-50 प्रतिशत)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, समेकित एकीकृत वाटर सेड प्रबंधन कार्यक्रम इत्यादि
निम्न महत्व (5-25 प्रतिशत)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना इत्यादि
सीमांत महत्व (5 प्रतिशत से कम)	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी, पर्यावरण स्वयंसेवी कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री इत्यादि

टिप्पणी : योजनाओं की सूची सिर्फ सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं।

टिप्पणी:

- पर्यावरणीय स्थिरता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम संबंधी बजट अनुमानों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।

- हरित बजट में केवल चुनिंदा विभागों के बजट अनुमानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के आवंटन एवं व्यय को ही शामिल किया गया है, इसलिए परिणाम या व्यय पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं।
- पर्यावरण नियमों को बजट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान कार्यप्रणाली में हरित बजट पर्यावरणीय स्थिरता हेतु व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।
- उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद, इस प्रक्रिया से संबंधित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण नीति, सार्वजनिक वित्त और बजट, हरित अर्थव्यवस्था आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को एकत्र करने की संभावना है।

4. बिहार में हरित बजट : सारांश

बिहार में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन और उससे निपटने की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा महसूस किया जाता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 से ही राज्य सरकार द्वारा हरित बजट तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार के हरित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को पर्यावरणीय महत्व, थीम एवं सतत् विकास लक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता हेतु किए गए समेकित व्यय संबंधी दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। वर्तमान खंड में बिहार में वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार के लिए हरित बजट आवंटन पर चर्चा की गई है।

हरित बजट का सारांश तालिका 3 में दिया गया है। वर्ष 2024–25 में हरित बजट के लिए कुल 13,823.39 करोड़ रु. अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के 9920.77 करोड़ रु. के बजट आवंटन से 39.34 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024–25 में हरित बजट, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.42 प्रतिशत और राज्य के कुल बजट का 4.96 प्रतिशत है।

विभाग–वार हरित बजट

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में कुल 20 विभागों द्वारा हरित योजना संबंधी विवरणी उपलब्ध कराए गए। अनुसूची 1 में चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों को उनके हरित प्रासंगिकता, गतिविधियों, तथा सतत विकास लक्ष्यों, के साथ टैगिंग करते हुए विवरणी प्रस्तुत किया गया है। वहीं, 2024–25 के लिए विभाग का कुल बजट, चिन्हित योजनाओं का बजट तथा हरित बजट आवंटन की विवरणी तालिका 4 में दिया गया है। पर्यावरण संबंधी योजना/कार्यक्रम, व्यय एवं आवंटन के नजरिए से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरित बजट का महत्वपूर्ण अंग है।

पर्यावरण संबंधी योजनाओं का महत्व

पर्यावरण संबंधी पूर्ण, आंशिक या सीमांत प्रभावों के आधार पर योजनाओं का वर्गीकरण किया गया है, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति उनके योगदान का मूल्यांकन में मदद मिलती है। इस वर्ष का हरित बजट आवंटन मुख्यत: श्रेणी ए – पूर्णत: समर्पित (90–100 प्रतिशत) और श्रेणी सी– उच्च महत्व (50–75 प्रतिशत) के अंतर्गत है, जिनकी कुल राशि क्रमश: 6514.08 करोड़ रु. और 3759.62 करोड़ रु. है (तालिका 7)। पूर्णत: समर्पित श्रेणी के तहत कुल 90 योजनाओं की पहचान की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सभी योजनाएं ''पूर्णत: समर्पित'' श्रेणी में हैं। इसके बाद लघु जल संसाधन विभाग और नगर आवास एवं विकास विभाग का स्थान है। जल–जीवन–हरियाली अभियान, 2070 तक नेट–जीरो उर्त्सजन 'जलवायु अनुकूलन एवं निम्न कार्बन विकास–पथ', जैविक खेती को बढ़ावा, ई–वाहन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण जैसी विभिन्न पहलें राज्य के उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

सतत विकास लक्ष्य का विभाग–वार सूचीकरण

विभागीय स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी पहलों के सूचीकरण से सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता),

2 (शून्य भूखमरी), 15 (भूमि पर जीवन), 11 (सुस्थिर शहर और समुदाय), तथा 13 (जलवायु संबंधी कार्य) से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में पर्यावरणीय संवेदनशीलता का पता चलता है (तालिका 8 और चित्र 4)। जलवायु संबंधी कार्रवाई के साथ-साथ जल, खाद्य, जमीन, और नगर विकास पर फोकस पर्यावरण संबंधी अंतर्संबंधित मुद्दों की व्यापक समझ को रेखांकित करता है।

हरित बजट का थीम सूचीकरण

पर्यावरण की सुस्थिरता संबंधी विभिन्न थीमों में हरित बजट का आवंटन चित्र 5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2024-25 की हरित बजट निर्माण रणनीति में हरित अवसंरचना (24.65 प्रतिशत), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (19.24 प्रतिशत), हरित अर्थव्यवस्था एवं रोजगार (14.83 प्रतिशत), जमीन का सतत् उपयोग (14.03 प्रतिशत), तथा जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन (10.82 प्रतिशत) को प्राथमिकता दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों को व्यक्त करता है। शेष बजट को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन (6.61 प्रतिशत), वायु एवं जलवायु प्रदूषण में कमी (6.01 प्रतिशत), तथा जैव-विविधता एवं पारिस्थितिक संरक्षण (3.81 प्रतिशत) थीमों में बांटा गया है।

भविष्य की राहें

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बिहार जैसी अर्थव्यवस्था के लिए हरित बजट जैसे नए दृष्टिकोण की जरूरत है। पर्यावरण के व्यापक प्रभावों को देखते हुए संसाधन प्रबंधन एवं हरित अवसंरचना पर व्यय संबंधी निर्णय आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की स्थिरता को संतुलित करने की दिशा में कारगर होंगे। इस प्रकार, बिहार में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया की वर्तमान यात्रा से कुशलता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और हितधारकों की व्यापक संलग्नता बढ़ने की आशा की जाती है जो पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों की सुव्यवस्थित प्राप्ति के कारक होंगे।

तालिका 3: बिहार में हरित बजट सारांश

(करोड़ रु. में)

विवरणी	वास्तविक			बजट अनुमान	
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य का बजट परिव्यय	165696.51	193122.98	231903.88	261885.40	278725.72
राज्य की कुल प्राप्ति (राजस्व प्राप्ति+ पूंजीगत प्राप्ति)	164903.84	199270.15	221013.04	262085.40	278925.72
राजस्व प्राप्ति	128168.35	158797.33	172688.02	212326.97	226798.40
केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्ति	91625.29	119958.45	124535.39	156115.18	165172.54
राज्य का अपना राजस्व	36543.05	38838.88	48152.64	56211.79	61625.86
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	618628.00	675448.00	751396.00	858928.00	976514.00
चिन्हित विभागों का बजट आवंटन	83682.31	104428.61	129321.06	79074.38	152350.86
चिन्हित विभागों का हरित बजट आवंटन	3307.59	6767.29	7989.58	9920.77	13823.39
चिन्हित विभागों के कुल बजट में हरित बजट का हिस्सा (%)	3.95	6.48	6.18	12.55	9.07
राज्य के कुल बजट में हरित बजट का हिस्सा (%)	2.00	3.50	3.45	3.79	4.96
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हरित बजट का हिस्सा (%)	0.53	1.00	1.06	1.16	1.42

स्रोत : बजट सारांश, बिहार सरकार (विभिन्न संस्करण)

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरित बजट विभाग-वार विवरणी

(करोड़ रु. में)

क्र.	विभाग[1]	हरित बजट का अनुमान (2024-25)				
		विभाग का कुल बजट	चिन्हित योजना का बजट	चिन्हित योजना का हरित बजट	कुल बजट आवंटन का हरित %	चिन्हित योजना का हरित %
1	कृषि	3600.92	1211.95	643.74	17.88	53.12
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1631.35	312.89	182.32	11.18	58.27
3	भवन निर्माण	5012.65	1115.00	156.75	3.13	14.06
4	शिक्षा	52639.03	1173.02	35.29	0.07	3.01
5	ऊर्जा	11422.68	270.00	270.00	2.36	100.00
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	853.03	853.03	853.03	100.00	100.00
7	स्वास्थ्य	14932.09	3.50	3.50	0.02	100.00
8	उद्योग	1833.09	501.53	343.55	18.74	68.50
9	सूचना एवं जनसंपर्क	254.24	81.13	4.06	1.60	5.00
10	लघु जल संसाधन	1030.95	785.00	785.00	76.14	100.00
11	पंचायती राज	11025.84	5733.86	4110.03	37.28	71.68
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1848.22	50.00	50.00	2.71	100.00
13	पथ निर्माण	5702.81	1379.00	9.74	0.17	0.71
14	ग्रामीण विकास	14296.71	8142.71	4383.88	30.66	53.84
15	ग्रामीण कार्य	9532.31	4778.13	149.28	1.57	3.12
16	गन्ना उद्योग	123.80	37.60	37.60	30.37	100.00
17	पर्यटन	462.44	162.00	35.25	7.62	21.76
18	परिवहन	451.46	131.00	102.00	22.59	77.86
19	नगर विकास एवं आवास	11298.72	3408.10	1118.30	9.90	32.81
20	जल संसाधन	4398.52	3232.63	550.09	12.51	17.02
	योगफल	**152350.86**	**33362.08**	**13823.39**	**9.07**	**41.43**

37 वैसे विभाग जिनके कार्य का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा संधारणियता स्थापित करना है, उनके वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनायों/कार्यक्रमों में स्थापना एवं प्रतिब) व्यय दोनों की राशि को शामिल किया गया है।

तालिका 5: बिहार में हरित बजट का विभाग-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.	चिन्हित विभाग	2022-23 हरित बजट (वास्तविक)	2023-24 हरित बजट अनुमान	2023-24 हरित बजट पुन. अनुमान	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 हरित बजट अनुमान
1	कृषि	569.89	968.50	663.45	1211.95	643.74
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	138.11	179.18	187.42	312.89	182.32
3	भवन निर्माण	112.74	73.88	89.10	1115.00	156.75
4	शिक्षा	9.97	16.21	46.39	1173.02	35.29
5	ऊर्जा	42.50	70.00	70.00	270.00	270.00
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	518.75	773.84	811.65	853.03	853.03
7	स्वास्थ्य	0.77	5.00	5.00	3.50	3.50
8	उद्योग	1.21	1.75	2.19	501.53	343.55
9	सूचना एवं जनसंपर्क	4.11	4.10	4.10	81.13	4.06
10	लघु जल संसाधन	466.12	784.58	799.43	785.00	785.00
11	पंचायती राज	2306.37	0.00	2330.49	5733.86	4110.03
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	21.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13	पथ निर्माण	11.16	47.99	56.33	1379.00	9.74
14	ग्रामीण विकास	2476.84	4742.66	5004.79	8142.71	4383.88
15	ग्रामीण कार्य	137.58	325.04	400.08	4778.13	149.28
16	गन्ना उद्योग	14.45	100.00	100.00	37.60	37.60
17	पर्यटन	19.53	26.99	26.99	162.00	35.25
18	परिवहन	5.24	66.55	66.55	131.00	102.00
19	नगर विकास एवं आवास	574.61	1132.22	5393.28	3408.10	1118.30
20	जल संसाधन	558.61	552.29	686.31	3232.63	550.09
	योगफल	**7989.58**	**9920.77**	**16793.54**	**33362.08**	**13823.39**

तालिका 6: हरित बजट के लिए चिन्हित कुल योजनाएँ

क्रं.	विभाग	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता												चिन्हित योजनाएं 2024-25
		90-100%		75-90%		75-50%		50-25%		25-05%		< 05%		
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	
1	कृषि	3	3	16	4	19	21	21	12	6	15	0	0	65
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	1	1	13
3	भवन निर्माण	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	7
4	शिक्षा	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	8	3
5	ऊर्जा	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	पर्या. वन एवं जल. परिवर्तन	39	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
7	स्वास्थ्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	उद्योग	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2
9	सूचना एवं जनसंपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	लघु जल संसाधन	12	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
11	पंचायती राज	3	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	12
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
14	ग्रामीण विकास	9	8	0	0	8	2	0	0	17	0	0	17	34
15	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	6
16	गन्ना उद्योग	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
18	परिवहन	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	2
19	नगर विकास एवं आवास	13	5	6	6	0	0	16	4	17	14	0	3	52
20	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	0	0	22
	कुल	**90**	**74**	**22**	**13**	**39**	**32**	**49**	**24**	**68**	**55**	**13**	**39**	**281**

तालिका 7: बिहार में हरित बजट का प्रदर्शन (2024-25)

समूह	योजनाओं की संख्या हरित बजट	कुल हरित बजट (करोड़ रु.)
ए- पूर्णतः समर्पित (90-100%)	90	6514.08
बी- अत्यधिक महत्व (75-90%)	22	148.77
सी- अधिक महत्व (50-75%)	39	3759.62
डी- मध्यम महत्व (25-50%)	49	1987.99
इ- निम्न महत्व (5-25%)	68	1267.95
एफ- सीमांत महत्व (05% तक)	13	144.98
कुल	**281**	**13823.39**

तालिका 8: विभागवार एस0डी0जी0 मैपिंग

क्रं.	विभाग	एस.डी.जी. 2	एस.डी.जी. 4	एस.डी.जी. 5	एस.डी.जी. 6	एस.डी.जी. 7	एस.डी.जी. 8	एस.डी.जी. 9	एस.डी.जी. 11	एस.डी.जी. 12	एस.डी.जी. 13	एस.डी.जी. 14	एस.डी.जी. 15
1	कृषि	55	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	32
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	7	6
3	भवन निर्माण	0	0	0	4	4	0	2	4	4	4	0	1
4	शिक्षा	0	1	0	0	2	0	2	0	0	3	0	0
5	ऊर्जा	0	0	0	3	1	0	1	0	3	0	0	0
6	पर्या. वन एवं जल. परिवर्तन	4	1	0	0	0	10	2	4	0	17	2	30
7	स्वास्थ्य	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	उद्योग	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
9	सूचना एवं जनसंपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	लघु जल संसाधन	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
11	पंचायती राज	0	0	0	9	6	0	0	12	0	6	0	9
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	ग्रामीण विकास	0	0	23	11	0	25	0	0	0	2	0	10
15	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6
16	गन्ना उद्योग	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	पर्यटन	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
18	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
19	नगर विकास एवं आवास	0	0	0	39	8	0	3	49	5	8	0	3
20	जल संसाधन	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**109**	**2**	**23**	**142**	**21**	**35**	**11**	**71**	**20**	**51**	**9**	**100**

चित्र 4: विभागवार एसडीजी वितरण

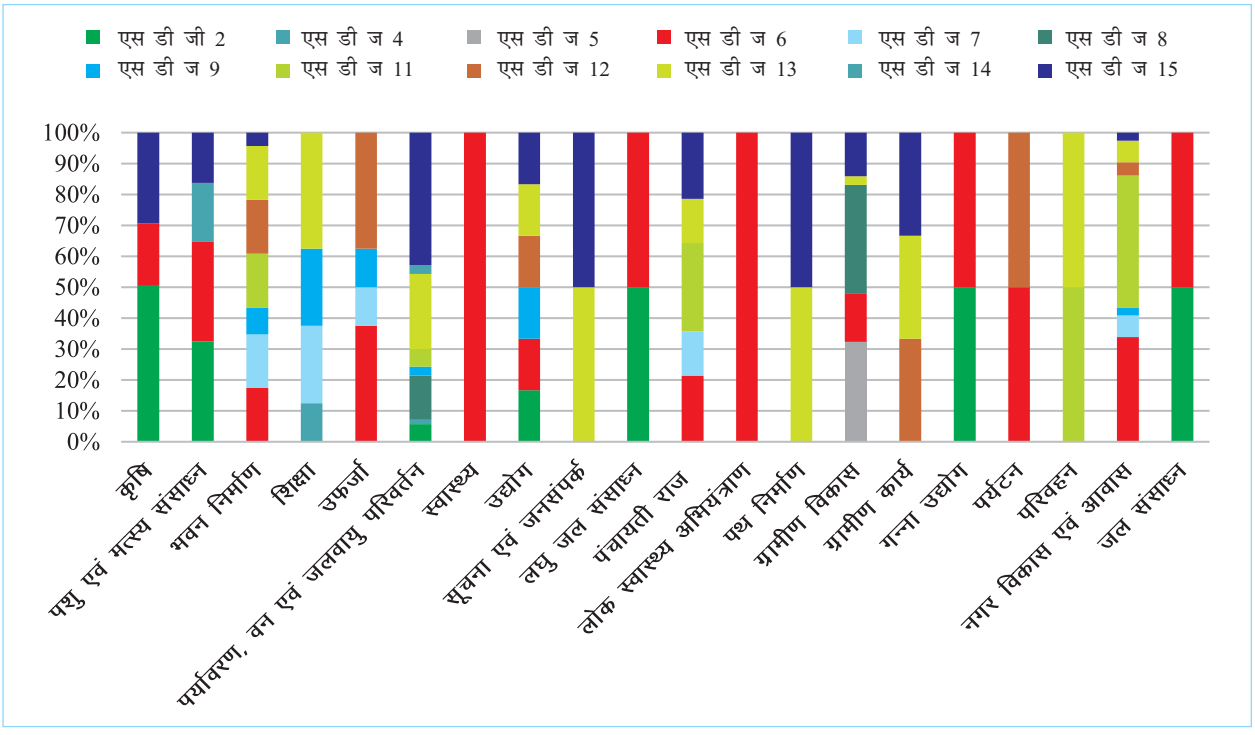

चित्र 5: विभागवार गतिविधि वितरण

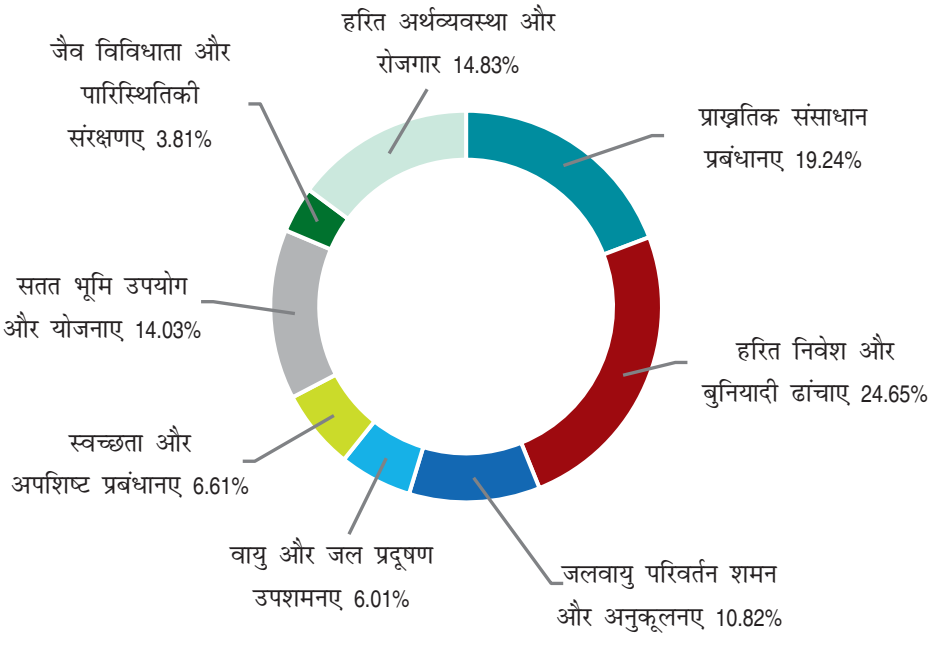

5. राज्य में मुख्य हरित पहलें

पर्यावरण की सुस्थिरता और जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न पहलों की घोषणा की है। इस खंड में राज्य में ली गई मुख्य हरित पहलों पर चर्चा की गई है।

1. कृषि विभाग

- **चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28) :** अक्तूबर 2023 में आरंभ हुए चतुर्थ कृषि रोडमैप में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कृषि, कृषिवानिकी, फसल अपशिष्ट जलाने पर रोकथाम, जैविक खेती एवं जैव उर्वरक को प्रोत्साहन तथा जैविक कॉरिडोर की योजना जैसी हरित कार्यक्रमों के साथ सतत कृषि विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। राज्य सरकार की इन पहलों से संसाधनों के उपयोग में सुधार और मिट्टी की स्वास्थ्य रक्षा होती है। साथ ही, सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों, वर्षा जल संचयन, और समेकित जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है तथा किसानों की आजीविका में सुधार हो सकता है।

- **हरित योजनाओं को बढ़ावा :** विभाग के बजट का बड़ा हिस्सा हरित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। फसल उत्पादन योजनाओं जैसे- धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मोटे अनाज तथा व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, जूट इत्यादि उगाने को प्राथमिकता दी जाती है। फसल उत्पादन के घटकों श्री विधि धान की खेती, जीरो टिलेज से धान एवं गेहूँ की खेती, पैडी ट्रासप्लांटर से धान की रोपाई इत्यादि शामिल है। राज्य में जैविक कॉरिडोर योजनान्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसल अंतर्गत एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसलों का क्षेत्र विस्तार की योजना कार्यान्वित की जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर बल दिया जा रहा है। ड्रीप सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है।

- **जैविक कॉरीडोर योजना :** जैविक कॉरीडोर योजना का लक्ष्य गंगा के आसपास के जिलों को 20,000 एकड़ जमीन को जैविक क्षेत्र में बदलना है। इस योजना के तहत मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, भू-जल का प्रदूषण से बचाव, रसायनों के प्रभाव से मिट्टी, पानी और हवा का बचाव, विषैली चीजों से रहित खाद्यानों का उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन लागत में कमी और अंतत: आमदनी और आहार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों को वित्तीय और अवसंरचना संबंधी सहायता देकर टिकाउ कृषि व्यवहारों को बढ़ावा दिया जाता है। बागवानी के तहत एकवर्षीय और बहुवर्षीय फसलों के क्षेत्र विस्तार की भी योजना है।

- **भूमि संरक्षण :** इस परियोजना में 'स्प्रिंकलर' योजनाओं, चेकडैम, नहरों का जीर्णोद्धार, तटबंध, स्टैच्यू गार्ड ट्रेंच, और वृक्षारोपण सहित भूमि और जल संरक्षण के लिए विभिन्न ढांचों का निर्माण, वृक्षारोपण शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, और भूमिहीन किसानों के लिए उत्पादन प्रणालियां शामिल हैं।

- **समेकित जलसंभर क्षेत्र विकास कार्यक्रम :** समेकित जलसंभर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार जलसंभर क्षेत्र विकास समिति (बीडब्ल्यूडीएस) के जरिए किया जा रहा है। इसका लक्ष्य जलसंभर क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुधार है। इसमें सिंचाई के लिए वर्षाजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भूजल संभरण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, फसलों की उपज बढ़ाना, परितंत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना, और सामुदायिक आजीविकाओं में वृद्धि करना है। योजना का क्रियान्वयन बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, भागलपुर, बक्सर और बेगूसराय जैसे विभिन्न जिलों में किया जा रहा है।

2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- **मात्स्यिकी विकास के जरिए जल की गुणवत्ता और परितंत्र के स्वास्थ्य में सुधार :** इसकी महत्वपूर्ण योजनाओं में नए तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, मछली पालन तालाबों का विकास, समेकित तालाब प्रबंधन, जलाशय मात्स्यिकी विकास, आर्द्रभूमियों में पेन/केज का अधिष्ठापन आदि शामिल हैं। अनुपयुक्त भूमि एवं आर्द्रभूमियों में तालाब विकसित करने की योजना है जिससे भूजल का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ परितंत्रीय संतुलन बनाने और मछली पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। मात्स्यिकी विकास से जल की गुणवत्ता बरकरार रखने और उसके जरिए जैव-विविधता बढ़ाने तथा परितंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इनके तकनीकी विवरणों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के लिहाज से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना :** इस योजना का लक्ष्य राज्य में निजी और सरकारी चौरों (आर्द्रभूमियों) के समेकित विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए चौर विकास का समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें मछली का उत्पादन, कृषि, बागवानी, और कृषिवानिकी शामिल हैं। इससे अन्य कृषि उत्पादों के साथ-साथ 50,000 टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के समेकन से मछली पालकों के लिए नई संभावनाएं उपलब्ध होंगी जिससे उनके रोजगार और आमदनी को बल मिलेगा। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 873.19 लाख रु. के वित्तीय परिव्यय से 346.41 हेक्टेयर चौर क्षेत्रों का विकास किया गया।

3. भवन निर्माण विभाग

- **पर्यावरण के अनुकूल निर्माण :** राज्य में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ईंटों की जगह फ्लाई ऍश की ईंटों का उपयोग, सोलर पैनलों और मलजल उपचार संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा जैसी अनेक पहलें की जा रही हैं। निर्माण के कारण प्रभावित पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना और नए पेड़ लगाना राज्य में वानिकीकरण संबंधी प्रयासों का हिस्सा है।

- **वर्षाजल संचयन को बढ़ावा :** भूजल संभरण के लिए निर्माणाधीन और निर्मित सरकारी भवनों में वर्षाजल

संचयन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक तय लक्ष्य को पूरा करते हुए सरकारी आवासीय और अनावासीय भवनों में लगभग 6790 रूफटॉप इकाइयों को लगाने का काम पूरा किया गया गया।

- **ऊर्जा बचाने के उपायों का उपयोग :** ऊर्जा की खपत घटाने के लिए राज्य में दक्षता संबंधी उच्च रेटिंग वाले एलईडी बल्ब और वातानुकूलकों के साथ-साथ समय पर ऑफ हो जाने वाले विद्युत उपकरणों/ बल्बों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में सरकारी भवनों और कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जिसे बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है और सरकारी भवनों से भिन्न भवनों के लिए ब्रेडा द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' दिया जा रहा है। प्रकाश और वातानुकूलन के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए विभाग गत कुछ वर्षों से अपने प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक भवन परियोजनाओं में हरित अवधारणाओं को शामिल कर रहा है। हरित भवन अवधारणा का उपयोग करके निर्माण करने के लिए पटना स्थित बिहार संग्रहालय को समेकित पर्यावास मूल्यांकन (गृहा) द्वारा हरित रेटिंग के तहत चार-सितारे (फोर स्टार) दिए गए हैं। पटना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी को गृहा द्वारा पांच सितारे मिलना तय है। नई दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन का निर्माण हरित अवधारणा के आधार पर किया गया है जिसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए उदग्र वातानुकूलन प्रणाली और गर्म जल की आपूर्ति के लिए सोलर हीटर का उपयोग किया गया है।

- **नेट जीरो अपशिष्ट निस्स्राव प्रणाली :** कुछ भवनों में नेट जीरो अपशिष्ट निस्स्राव प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है जिससे प्रयुक्त गंदे पानी को उपचारित करने के बाद उसका उपयोग शौचालय में फ्लश करने और बागवानी के लिए हो पाता है। स्वच्छता और अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की बर्बादी में कमी के लिए सरकारी भवनों और कार्यालयों के स्नानागारों और शौचालयों में सेंसर लगाए जा रहे हैं जबकि भूजल को नियंत्रित रखने के लिए वैकल्पिक बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है।

4. ऊर्जा विभाग

- **बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) :** गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास देश में 1970 के दशक में तेल के कारण लगे झटकों के चलते उर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ वातावरण की जरूरत पर तथा ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए वाहकों के बतौर नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया गया। ब्रेडा नवीकरणीय उर्जा संबंधी नीतियों का निर्माण और निष्पादन करने, लक्ष्य निर्धारित करने, सब्सिडी देने और विनियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करता है। वित्तवर्ष 2024-25 के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- **ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की छतों पर 25 मेगावाट पीक ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 127 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

- **ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड-संपर्कित/ हाइब्रिड संयंत्रों में बदलना :** मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत 3.08 मेगावाट पीक ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड संपर्कित/ हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों में बदला जाएगा जिस पर राज्य सरकार के कुल 2.70 करोड़ रु. व्यय होंगे। इसमें पंचवर्षीय व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी) के जरिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य और नेट मीटिरिंग भी शामिल किया गया है।

- **सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना :** राज्य में 500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1.95 करोड़ रु. का व्यय किया जाना है।

- **ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना :** इस प्रस्ताव में आपात प्रयोजनों के लिए 1 मेगावाट पीक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शामिल है जिसके लिए राज्यांश 1.60 करोड़ रु. है।

- **बिहार राज्य जलविद्युत निगम :** बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) जलविद्युत की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार का पर्यवेक्षण करता है। अभी राज्य में 13 अतिलघु और लघु जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगवाट की है। निगम अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, सुपौल और पश्चिम चंपारण में 11 और अतिलघु जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है जिनकी कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है।

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के शमन, प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोतों यथा नदी, तालाब, आर्द्रभूमि, पर्यावरण, वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा इत्यादि के लिये प्रतिबद्ध है। हरित अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्ष्य को निर्धारित कर योजनाओं का सूत्रण किया जा रहा है। इस हेतु वानिकी समर्पित आजीविका यथा कृषि वानिकी, निजी पौधशालाओं की स्थापना, पौधारोपण, ईको-टूरिज्म, पार्क विकास एवं प्रबंधन इत्यादि के माध्यम से रोजगार तथा हितधारकों को आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **जल-जीवन-हरियाली अभियान :** राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण की पुनर्स्थापना और समग्र सतत विकास की प्राप्ति के लिए लक्षित व्यापक कार्यक्रम है। विभाग वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन के लिए सक्रियतापूर्वक व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। हरित आच्छादन और पर्यावरण का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप और जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वनीकरण के विभाग के प्रयासों में हितधारकों को शामिल किया गया है।

- **प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी**

  - जल-जीवन-हरियाली अभियान के अलावा, राज्य के नहरों/नदी तटबंधों और सड़कों किनारे तथा जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों को जोड़नेवाली सड़कों पर में वृक्षारोपण और वानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के तहत किसानों की रैयती जमीन पर वृक्षारोपण और पौधशालाएं लगाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और फर्नीचर तथा अगरबत्ती जैसे बांस उत्पादों के निर्माण के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

  - **कैंपा प्राधिकरण :** भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण के माध्यम से वनों के विकास एवं मृदा जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसका लक्ष्य गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वनभूमि के उपयोग से हुए पारिस्थितकीय क्षति की क्षतिपूर्ति करना है। कैंपा निधि का 80 प्रतिशत राशि का उपयोग वनीकरण और वन्यजीव पर्यावास में सुधार के लिए और शेष राशि का उपयोग अवसंरचना और क्षमता निर्माण के लिए किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल 1.59 लाख पौधारोपण के लक्ष्य विरूद्ध 1.53 लाख पौधे लगाए गए जबकि 2023-24 में अभी तक 18.89 लाख पौधे लगाए जाने हैं।

- **गारलैंड ट्रेंचिंग :** जल और जैव-विविधता के संरक्षण के लिए बिहार के दक्षिणी जिलों के वनों में गारलैंड ट्रेंचिंग की योजना शुरू की गई है। इसके तहत 6.69 लाख घनमीटर से भी अधिक वर्षाजल संग्रहित करके इन महत्वपूर्ण परितंत्रों के संरक्षण के लिए योगदान किया गया है।

- **प्राकृतिक वनों का विकास :** अनुशंसित वनभूमि पर मौजूद पेड़-पौधों के रखरखाव के साथ-साथ मिट्टी और जल संरक्षण के प्रयास और गार्लैंड ट्रेंचिंग की जा रही है।

- **प्लांट टिस्सू कल्चर प्रयोगशाला :** प्रयोगशाला की स्थापना और विकास के जरिए गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार करने की योजना है जिनका उपयोग वृक्षारोपण कार्य में किया जा सके।

- **राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एसएपीसीसी) :** पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का प्राकृतिक संसाधनों और जैव-विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पेरिस समझौते में गर्म हो रही धरती के औसत तापमान वृद्धि को 1.50 सेल्सियस के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व के सभी देशों में इनके दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (State Action Plan on Climate Change- SAPCC) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु विवरणी और Vulnerability Assessment को बिहार मौसम सेवा केन्द्र, योजना एवं विकास विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है।

- **जलवायु अनुकूल एवं निम्न कार्बन विकास-पथ :** देश की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के अनुरूप बिहार को 2070

तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए व्यापक रणनीति के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, परिवहन, और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन का विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक एवं अनुमानित परिदृष्यों के आधार पर कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, मानव स्वाास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के लिए अरक्षितता विवरणी (Vulnerability Profile) विकसित करने पर फोकस किया गया है।

- **जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला (Climate Change Learning Lab) :** वर्ष 2022 में शुरू की गई यह प्रयोगशाला जर्मन विकास अभिकरण, GIZ द्वारा सहायता-प्राप्त संवाद मूलक प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य बिहार में जलवायु परिवर्तन के साथ खास तौर से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है।

- **आर्द्र-भूमि संरक्षण एवं विकास :** राष्ट्रीय आर्द्र-भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस (2021) में बिहार में 2.25 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली 4526 आर्द्र-भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के **जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्र-भूमि शाखा** तथा **स्टेट वेटलैंड ऑथरिटी** रामसर साईट सहित आर्द्र-भूमियों की पहचान और विकास करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रथम चरण में 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 133 आर्द्र-भूमियों को प्राथमिकता दी गई है। आर्द्र-भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली 2017 के अनुरूप इनमें से 60 आर्द्र भूमियों के संक्षिप्त दस्तावेज और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके उन्हें वेटलैंड इंडिया पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

- **एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध :** राज्य में प्लास्टिक के कैरी बैग और एकल उपयोग में आने वाले अन्य प्लास्टिक के सामानों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया गया है जिसका लक्ष्य प्रदूषण के न्यूनीकरण एवं पर्यावरण की रक्षा करना है। वर्ष 2018 से राज्य के सभी स्थानीय नगर निकायों एवं पंचायतों में लागू है। यह प्रतिबंध 2022 में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 और पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय की 2021 की अधिसूचना के अनुरूप है।

- **इको-टूरिज्म और पार्कों का विकास :** सभी जिलों में पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास तथा समग्र परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पार्कों के विकास के लिए अनेक पहलें की गई हैं। राजगीर में 250 एकड़ क्षेत्रफल में फैला नेचर सफारी तथा 480 एकड़ क्षेत्रफल में फैला जू-सफारी राज्य में इको-टूरिज्म के दृष्टिकोण से पहला सफारी पार्क है। इससे एक तरफ जहां काफी संख्या में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पारिस्थितिकीय विकास को बल मिल रहा है।

- **प्रदूषण नियंत्रण :** राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं।

  - **परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण (Ambient Air Quality Monitoring):** बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के

जरिए परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर देशी तकनीक के उपयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 38 जिलों में 534 प्रखंडों में कम लागत वाली संवेदी यंत्र सेंसर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पटना में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में भी संवेदी यंत्र स्थापित किया गया है। इन यंत्रों के आंकड़ें और उपग्रहीय आंकड़ों का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है। यह परियोजना तीन-वर्षीय शोध एवं विकास कार्यक्रम का हिस्सा है।

- **शोर का अनुश्रवण :** लाउडस्पीकर, परिवहन वाहनों, निर्माण गतिविधियों, जेनरेटर सेट, उद्योगों, और आतिशबाजियों जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया जा रहा है जिससे दिन और रात, दोनो में स्वस्थ ध्वनि स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

♦ **वन्यजीव सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन**

- **वन्यजीव पर्यावास विकास कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका फोकस राज्य में अभयारण्यों और बाहरी क्षेत्रों में अवस्थित वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन, तथा मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच टकराव बचाने पर है।

- **विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य :** देश का एकमात्र डॉल्फीन (सूंस) अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। वर्ष 2018-19 में गंगा, गंडक, कोशी, परमार, मेची और महानंदा नदियों में किए गए सर्वेक्षण में 1464 डॉल्फीनों का पता चला था। इस अभयारण्य का विस्तार भागलपुर जिले में गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर में है।

- **वाल्मीकि बाघ आरक्ष :** यह परियोजना बहुमुखी पहल है जिसका लक्ष्य वनों, वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों की रक्षा करना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित हैं। वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम के लिए राज्यांश 371.10 लाख रु. और केंद्रांश 1112.00 लाख रु. था। परियोजना का लक्ष्य वनों की रक्षा, आरक्ष क्षेत्र का प्रबंधन, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवैध शिकार और वन्य अपराधों पर रोक लगाना तथा बाघ आरक्ष में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।

- **गज परियोजना :** इसके तहत हाथियों के पर्यावास की रक्षा के लिए पश्चिम चंपारण जिले में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। इसका लक्ष्य वनों में हाथियों के प्रवास के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण है। हाथियों की रक्षा, संरक्षण और समीपवर्ती राज्यों से आने वाले हाथियों के साथ मनुष्यों

के टकराव पर नियंत्रण के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना एवं गज परियोजना को संयुक्त कर एकल योजना- प्रोजेक्ट टाईगर एवं गज क्रियान्वित की जा रही है।

6. स्वास्थ्य विभाग

- **स्वास्थ्य केंद्रों का हरितीकरण :** बिहार के जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में जल सुरक्षा एवं सुस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों में वर्षाजल संग्रहण की व्यवस्था की गई है।
- **समेकित पर्यावास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) द्वारा हरित भवन :** राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और सुस्थिर स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों के निर्माण के लिए हरित रेटिंग प्रणाली वाली गृहा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) हरित भवन क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

7. उद्योग विभाग

बिहार जैव-इंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति (2023)

- राज्य सरकार द्वारा बिहार ईथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की जगह बिहार जैव-इंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाया गया है जिसके तहत राज्य में कुल 17 ईथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रीन-फील्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैंडअलोन ईथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन इकाइयों का राज्य में सर्वांगिण विकास करना और उनके निवेशकों, किसानों तथा अन्य संलग्न हितधारकों को लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय जैव-इंधन नीति 2018 और राष्ट्रीय जैव-इंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत इकाइयों के लिए शत प्रतिशत ईथेनॉल और दाबित बायोगैस का उत्पादन करना अनिवार्य है।
- इस नीति के तहत राज्य में सिर्फ इंधन श्रेणी के ईथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई इकाइयों और कम्प्रेस्ड बायोगैस/बायो-सीएनजी इकाइयों के लिए अनुदान के लाभों के अलावा सुविधाओं और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- इसका मुख्य लक्ष्य ईथेनॉल और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले किसानों एवं संलग्न फीड-स्टॉक की आय बढ़ाना है। साथ ही, इंधन श्रेणी स्टैंडअलोन इकाइयों और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

8. लघु जल संसाधन विभाग

- **बड़े तालाबों और आहर-पइनों को पुनर्जीवित करना :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पूरे राज्य में

एक एकड़ से अधिक रकवा वाले आहर-पइनों और पांच एकड़ से बड़े रकवा वाले तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही, चेक डैम/ वीयर और नालों का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक भूमि पर बड़े वॉटर बॉडिज एवं पहाड़ों की तलहटी में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सिंचाई सुविधाओं, वर्षाजल संचयन और भूजल पुनर्भरण का कार्य हो सकेगा।

- **सिंचाई सुविधाएं :** फसलों की उपज और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जल-जीवन-हरियाली अभियान और 'हर खेत को सिंचाई का पानी' योजनान्तर्गत अभी तक 2143 आहर-पइन/ उद्वह सिंचाई/ गारलैंड ट्रेंच और तालाब की योजनाएं पूरी की गई हैं और 288 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं से 2,41,501 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 992 लाख घनमीटर जल संचयन क्षमता बहाल करने में मदद मिली है। वर्ष 2023-24 में अभी तक आहर-पइन/ तालाब/ चेक डैम और उद्वह सिंचाई की 729 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

- **अन्य क्रियाकलाप :** वॉटर बॉडिज में जल संचयन किया जायेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई की कमी वाले समय (Lean Period) में सिंचाई कार्य में होगा, भू-गर्भ जल का पुनर्भरण होगा साथ ही मछली पालन भी किया जा सकेगा।

9. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी)

- **पर्यावरण-अनुकूल निर्माण :** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन योजनाओं में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना के प्रारंभिक चरणों से ही ऐसे सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसके साथ-साथ योजना स्थल के आस-पास वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **भू-जल संरक्षण :** विभाग कार्बन प्रच्छादन (सिक्वेस्ट्रेशन) और पर्यावरण की पुन:स्थापना के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है जबकि सार्वजनिक कुँओं और सोख्ता गड्ढे वर्षाजल संचयन और भू-जल संभरण को बढ़ावा देते हैं जिससे जल संरक्षण बढ़ता है।

- **सामुदायिक संलग्नता :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हर महीने के पहले वृहस्पतिवार को वार्ड स्तर पर जल चौपाल बैठकों के आयोजन से जल संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ती है, जिससे पेयजल की बर्बादी घटती है और स्वच्छ जल बढ़ता है।

10. पथ निर्माण विभाग

आधारभूत संरचना विकास के मामले में खास कर सड़क निर्माण क्षेत्र में बिहार तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य सामाजिक और पर्यावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तीव्र शहरीकरण, मानववास स्थल में बदलाव को गति दे रहा है, जिससे भूमि उपयोग, जल की गुणवत्ता में ह्रास, जैव विविधता में ह्रास, प्रदूषण में वृद्धि एवं मानव

स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों में बढ़ोत्तरी हुई है। उच्च जनसंख्या घनत्व और पथ निर्माण के लिए जमीन की बढ़ती मांग ने पर्यावरण जोखिम में वृद्धि हुई है। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा पथ निर्माण परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर होनेवाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :-

- **वृक्ष संरक्षण को प्राथमिकता :** इसके तहत सड़कों के एलाइन्मेंट को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है कि पेंड़ नहीं कटे या कम-से-कम पेड़ कटें। पेंड़ कटने की स्थिति में क्षतिपूरक वनारोपण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को राशि का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित मार्ग से अलग हटकर पेंड़ों की कटाई नहीं की जाती है तथा पेंड़ बचाने हेतु डिजाइन में बदलाव किए जाते हैं, जिससे पेड़ों की क्षति कम हो। वर्तमान में पेंड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने का कार्य भी किया जा रहा है।

- **वायु और जल गुणवत्ता अनुश्रवण :** परियोजना से संबंधित निविदा/ संविदा के दस्तावेजों में वायु, ध्वनि और पानी के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपाय भी शामिल किए जा रहे हैं ताकि वे संवेदकों को इन मानकों का पालन बाध्यकारी हो तथा इसका अनुश्रवण परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जाता है। सड़क निर्माण के दौरान भू-जल सिंचाई गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणालियों एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **ध्वनि प्रदूषण से बचाव :** आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, और धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए 'हॉर्न नहीं' के सूचना पट और शोर अवरोधक बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

- **पथ निर्माण के दौरान धूल का प्रबंधन :** सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर और हरे पर्दों का उपयोग किया जा रहा है ताकि धूल नहीं उड़े। वहीं, क्रशर का उपयोग करते समय भी धूल उड़ने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली लगाई जाती है।

11. ग्रामीण विकास विभाग

- **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :** इस जन जागरण अभियान में केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन और राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित किया गया है। इसके पहले चरण में 122.15 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए।

  लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण (2020-21 से 2024-25) में 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायीत्व बनाये रखते हुए ठोस एवं तरह अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से गांवों को ''पूर्णत: स्वच्छ'' बनाया जाना लक्षित है एवं ग्राम पंचायतों को ओडीएफ-प्लस की हैसियत दिलाना है।

  दूसरे चरण में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता उपलब्ध हो। नवंबर 2023 तक 13.25 लाख लाभार्थियों अपने लिए शौचालयों का खुद निर्माण कराया है। अभियान के दूसरे

चरण में 2020–21 से 2024–25 तक की अवधि में 6 लाख शौचालयों, 533 सामुदायिक स्वच्छता इकाइयों तथा एक परिसर एवं मलजल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के निर्माण की और जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। परियोजना के तहत प्रबंधन, दूषित जल प्रबंधन, गीला कचरा प्रबंधन, औपचारिक शिक्षा और संचार के लिए 1506 करोड़ रु. के व्यय की जरूरत होगी।

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन :** इसमें मुख्यत: घर–घर से ठोस कचरे का संग्रहण और निष्पादन तथा नालियों की सफाई शामिल है। अभी 67,592 वार्डों में ठोस कचरे का घर–घर से संग्रहण करके निष्पादन किया जा रहा है जो ठोस अपशिष्ट के प्रति व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर पर कूड़ा इकट्ठा करने और उसके निपटान के लिए 5337 ई–रिक्शों और 73,147 पेडल रिक्शों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं, 3325 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (डब्ल्यूपीयू) की स्थापना से स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला है और दूर–दराज की लैंड–फिल पर भरोसा करने की जरूरत घटी है। साथ ही, तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 1.12 लाख सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है।

- **गोबरधन योजना :** इस योजना के तहत गाय–भैंस के गोबर और कृषि अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लि 14 गोबरर्धन इकाइयों के निर्माण से कृषि और पशु अपशिष्टों को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने में मदद मिली है।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) :** यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उत्पादक क्षमता में वृद्धि और दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार पैदा करने में सहायक रही है।

  - **जल संरक्षण :** आहर और पइन जैसे पारंपरिक वॉटर बॉडिस को पुनर्जीवित और संरक्षित करने से प्रभावी जल प्रबंधन हुआ है, जल–स्तर में वृद्धि हुई है, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है और निर्वनीकरण की प्रक्रिया रुकी है। इसी प्रकार, सामुदायिक और व्यक्तिगत लाभार्थियों के तालाबों के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण, पानी का दक्षतापूर्ण उपयोग, जल–स्तर बढ़ाने और मत्स्य पालन जैसी आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सुपौल और रोहतास जिलों में मनरेगा के तहत स्थानीय नालों की उड़ाही, सफाई और नहरों को स्थानीय नदियों के साथ जोड़ने के कई दृष्टांत ऐसे हैं, जिसे अन्य जगहों पर लागू करने की आवश्यकता है। इससे जल–जमाव की समस्या दूर करने में मदद मिली है। इससे कृषि, आजीविका और ग्रामीण आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा था। साथ ही, मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर चेक डैम निर्माण का कार्य भी किया गया है, जिससे सतही जल का व्यर्थ बहना रुका है और उसका भंडारण तथा सिंचाई के लिए उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

  - **वृक्षारोपण के जरिए हरित आच्छादन में वृद्धि :** मनरेगा के तहत एक प्रमुख गतिविधि वृक्षारोपण के जरिए हरित आच्छादन बढ़ाने की है। पौधों का चयन स्थानीय उपयोग के आधार पर किया जाता है और पौधों के बचाव के लिए घेराबंदी तथा वनपोषकों द्वारा देखरेख की जाती है। पौधे जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की नर्सरी' से लिए जाते हैं।

- **प्रदूषण न्यूनीकरण :** प्रभावी अपशिष्ट प्रसंस्करण, दुबारा उपयोग लायक चीजों के उपयोग और अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए अनेक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (डब्ल्यूपीयू) का निर्माण किया गया है।
- **भविष्योन्मुखी हस्तक्षेप :** जब तक नए विचारों और संभावनाओं का अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी रोजगार पैदा करने की प्रकिया के साथ-साथ बेहतर पर्यावरण के लिए भी योगदान होता है तब तक मनरेगा में उनका स्वागत है। प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन से संबंधित कार्यों का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) का व्यवस्थित और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

12. ग्रामीण कार्य विभाग

- **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 :** राज्य में ग्रामीण पथों की नियमित और व्यवस्थित मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गई है। इस नीति के तहत सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने के लिए प्रति पेड़ की दर से 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उसी समय और शेष 70 प्रतिशत राशि का पांच वर्षों तक रख-रखाव करने के बाद भुगतान किया जाता है, जिसमें मृत पौधों की संख्या घटा दी जायेगी। इससे राज्य में प्रभावी वृक्षारोपण सुनिश्चित होगा। वर्ष 2023-24 में लगभग 26,514.93 किमी सड़कों के दोनो ओर पेड़ लगाया गया है। अभी कुल 33,429.06 किमी लंबाई वाली 12,175 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा 2024-25 में लगभग 9000 किमी लंबाई में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य है।
- **सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग :** राज्य में कोलतार वाली सड़कों के निर्माण में कोलतार के 6 से 8 प्रतिशत वजन तक प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनो चरणों के तहत 4160.97 किमी की कुल लंबाई वाली कुल 1040 सड़कों का निर्माण स्वीकृत हुआ है जिसमें से 819 सड़कों (कुल लंबाई 2708.80 किमी) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

13. गन्ना उद्योग विभाग

- **बीज अनुदान :** मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य में चीनी मिलों के जरिए किसानों को रियायती दर पर ईख के 10 प्रभेदों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराकर ईख का उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ाना है। इन 10 चुनिंदा प्रभेदों के प्रमाणित बीज खरीदने के लिए सामान्य तबके के किसानों को प्रति क्विंटल 210 रु. और अनुसूचित जाति/जनजाति तबके के किसानों को 240 रु. प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाती है।

14. पर्यटन विभाग

- **इको-टूरिज्म की संभावना :** बिहार में 50 से भी अधिक बाघों का आश्रय स्थल रहे वाल्मीकिनगर बाघ आरक्ष के साथ-साथ नदियों, झीलों और जलाशयों को इको-टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। दक्षिण बिहार के कैमूर

और रोहतास जिले में अनेक जलाशय और जलप्रपात हैं जबकि मुंगेर, जमुई और बांका जिले नयनाभिराम दृश्यावलियों से संपन्न हैं। जलक्रीड़ा, नौकायन, ट्रैकिंग और साइकल मार्ग, रात्रि शिविर और मोटरसाइकल यात्रा आदि विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ सहयोग कर रहा है।

- **राजगीर में नए भवनों का निर्माण :** राजगीर में स्थापित नए एवं पुराने भवन रोपवे के पास पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके स्थान पर एक नया एकीकृत भवन बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान तथा उसके पश्चात वन्य प्राणी आश्रयणी सुरक्षित रह सके। इस भवन का उपयोग ईको पर्यटन के लिए किया जायेगा। राजगीर रज्जू मार्ग एवं उसके आस-पास क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण हेतु 16,38,73,000 रु. की योजना स्वीकृत है। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है।

- **राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटन ढांचों का विकास :** राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटन ढांचों के विकास के लिए 2023-24 में 11,43,15,000 रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें पार्किंग क्षेत्र, बूम बैरियर, प्रतीक्षा छावनी, पैविलियन, मुख्य प्रवेशद्वार, वाच टावर और राजगीर जू सफारी का प्रवेश दीवार शामिल हैं।

- **गुरपा पहाड़ पर पर्यटन विकास :** वर्ष 2023-24 में गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में स्थित गुरपा पहाड़ पर सुविधाओं के विकास की योजना है जिसके तहत 9,17,52,000 रु. के व्यय से तीर्थयात्री विश्रामगृह, शौचालय, साइनेज, हाइ मास्ट लाइट, संपर्क पथ, पुलिया और प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण शामिल है।

- **इको-टूरिज्म की भविष्य की योजनाएं :** पारिस्थितिक पर्यटन की योजनाओं के लिए प्रस्ताव विकसित किए जा रहे हैं जिनमें रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला, धुआं कुंड, मांझर कुंड, शेरशाह के किले के समीप पर्यटन विकास, तुतला भवानी मंदिर के समीप पर्यटन सुविधाओं का निर्माण, गुप्ताधाम में पर्यटन सुविधाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार तथा गया जिले में ढुंगेश्वरी पहाड़ी पर विशाल बुद्ध मूर्ति का निर्माण शामिल हैं।

15. परिवहन विभाग

- **बिहार स्वच्छ इंधन योजना**

  - **डीजल-चालित तिपहिया वाहन पर प्रतिबंध :** पटना नगर निगम और उसके आसपास के नगर निकायों यथा- दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद की सीमा में 31 मार्च, 2022 से डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इससे वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिली है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगमों की सीमा में भी 30 सितम्बर, 2023 से डीजल-चालित तिपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  - **स्वच्छ वाहनों को प्रोत्साहन :** इस योजना के तहत डीजल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन की जगह सीएनजी या बैटरी से चलने वाले तिपहिए खरीदने या पेट्रोल से चलने वाले तिपहियों/ मोटर कैब/

मैक्सी कैब में सीएनजी किट पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कुल 1505 लाभार्थियों के बीच 4,01,20,000 रु. का अनुदान दिया गया है।

- **पटना में डीजल-चालित सिटी बसों पर प्रतिबंध :** 30 सितंबर, 2023 से पटना और आसपास के शहरी क्षेत्रों में डीजल-चालित सिटी बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं 121 डीजल चालित बसों को सीएनजी बसों से प्रतिस्थापित कराने पर वाहन मालिकों को प्रति वाहन 7.50 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

♦ **वाहन उत्सर्जन में कमी**

- **12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर लगाना :** बिहार वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करके तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर तथा ट्रेलर को छोड़कर शेष निबंधित वाहनों की उम्र 12 वर्ष से अधिक हो जाने पर कुल कर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त हरित कर लगाने का प्रावधान किया गया है।

- **15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के परिचालन पर रोक :** जनहित को ध्यान में रखते हुए वाहनों द्वारा उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- **15 वर्ष से अधिक पुराने सभी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध :** पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद में अधिक प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन करने वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- **वाहन स्क्रैपिंग नीति :** वाहन जनित प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रकार के निबंधित वाहन जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथो बेच दिया गया है या किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यवसायिक वाहन जो परिचालन के योग्य हो परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते है, वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदण्ड में राहत देते हुए यह योजना लाई गई है।

♦ **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की डीजल बसों में परिवर्तन और सीएनजी बसों की खरीद :** राज्य में वायु प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभाग द्वारा 2019-20 से 2021-22 के बीच 41 डीजल बसों को सीएनजी बसों में बदल दिया गया है। वहीं, 2020-21 और 2021-22 में कुल 100 गैर-वातानुकूलित और 25 वातानुकूलित सीएनजी बसों की खरीद की गई। अभी बेड़े में 166 सीएनजी बसें चल रही हैं।

♦ **विद्युत बसों का परिचालन :** बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा 2020-21 से पटना के शहरी क्षेत्रों में

फेम–2 के तहत 25 विद्युत बसें चलाई जा रही है। इसके लिए कुल 104.58 करोड़ रु. के व्यय से मे0– अशोक लीलैंड से सात वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया है। सभी 25 विद्युत बसों को हरित इंधन से शक्ति मिलती है। इस परिवहन व्यवस्था का लक्ष्य परिवेशीय वायु गुणवत्ता बरकरार रखना है। इसके अतिरिक्त आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना के तहत राज्य के छः शहरों – पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां – के लिए सकल व्यय संविदा (जीसीसी) के तहत कुल 400 विद्युत बसें अधिप्राप्ति की योजना है। भारत सरकार को प्रस्तावित इस योजना को राज्य स्तर पर सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिल गई है।

- **विद्युत कारों का उपयोग :** वाहनों के उर्त्सजन से होने वाले प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभाग द्वारा विद्युत कारों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रथम चरण शुरू किया गया है और विद्युत वाहनों के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत छूट दी गई है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना :** वर्ष 2018 में शुरू इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन सुविधाएं और लोगों, खास कर वंचित तबकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के तहत वाहनों की खरीद पर हर पंचायत में चयनित लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रु. है। विभाग ने चयनित लाभार्थियों को ई–रिक्शा की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसकी अधिकतम सीमा 70,000 रु. है।

- **प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना :** वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी के लिए मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए लाइसेंस जारी करने हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। अभी तक राज्य में कुल 1488 प्रदूषण जांच केंद्र खोले गए हैं। प्रदूषण जांच किए गए वाहनों के आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वाहनों की जांच आसान बनाने के लिए वाहन जांच प्रमाण–पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं।

- **सीएनजी फिलिंग केंद्रों की स्थापना :** भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) ने पटना शहर में 27 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं तथा राज्य में कुल 106 सीएनजी स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इससे कारों और ऑटो को सीएनजी की आपूर्ति संभव हो पाती है। अतिरिक्त केंद्र निर्माणाधीन हैं और बेगूसराय में एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन शुरू किया गया है।

- **पथ कर में छूट :** सभी प्रकार के बैटरी–चालित वाहनों के लिए पथ कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

16. नगर विकास एवं आवास विभाग

- **नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन :** राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नाला निर्माण, सिवरेज निर्माण और अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का काम किया जा रहा है।

- **स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम (सात निश्चय-2) :** स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंतर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नगर निकायों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिससे जल निकासी के साथ तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल सके। पटना एवं इसके आस-पास के शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु कैचमेंट-01 से कैंचमेंट-09 तक की योजनाओं की स्वीकृति 957.51 करोड़ रू0 एवं सैदपुर नाला का जीर्णोद्धार योजना की स्वीकृति 259.81 करोड़ रू0 अनुमानित व्यय पर दी गई है। इसके अतिरिक्त 07 नगर निगम (दरभंगा, समस्तीपुर, आरा, पूर्णियां, सीतामढ़ी, बेतिया एवं छपरा) एवं 04 नगर परिषद् (मधेपुरा, शिवहर, जहानाबाद एवं बोधगया) क्षेत्र के लिए कुल 1034.67 करोड़ की स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- **जल-जीवन-हरियाली अभियान**

राज्य के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित 318 तालाबों/पोखरों के विरूद्ध 104 तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष तालाबों का जीर्णोद्धार प्रक्रियाधीन है। नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वामित्व वाले 429 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य, 9174 चापाकलों के निकट सोख्ता का निर्माण, 3336 कुँओं के निकट सोख्ता का निर्माण तथा 3744 कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया है।

- **स्वच्छ भारत मिशन**

इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत 407570 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 141 नगर निकायों में शत् प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण किया जा रहा है तथा कुल संग्रहित 5467 TPD (Ton per day) में से 25 प्रतिशत (1385 TPD) कचरे का प्रसंस्करण किया गया है। सुखे कचरे के प्रबंधन हेतु 35 नगर निकायों में 51 डम्प तथा गिले कचरे के प्रबंधन हेतु 87 नगर निकायों में 185 Waste to Compost केन्द्र संचालित है। पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए 05 TPD (Ton Per Day) के क्षमता का MRF Centre की स्थापना UNDP के सहयोग से की गई है। प्लास्टिक कैरी बैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम/समाप्त करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने हेतु बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) मॉडल उपविधि, 2022 में प्रावधान किया गया है।

- **अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)**

केन्द्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत राज्य के 20 नगर निकायों में पार्क निर्माण, 03 नगर निकायों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना तथा 21 नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित है। पार्क निर्माण के तहत वृक्षारोपण एवं हरित स्थल का विकास करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 24 पार्कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यह योजना दो नगर निकायों में पूर्ण हो चुकी है तथा एक में कार्य प्रगति पर है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भू-गर्भ जल संचयन एवं पुनर्भरण पीट भी बनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत stand Post भी लगेंगे, वहाँ रिचार्ज पीट भी बनाने का प्रावधान है।

- **पटना मेट्रो रेल निगम**

पटना में प्रस्तावित परियोजना में दो कॉरीडोर हैं। पहले को दानापुर से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना रेलवे स्टेशन और मीठापुर होते हुए खेमनीचक तक जाना है जिसकी कुल लंबाई 17.93 किमी है। दूसरे कॉरीडोर को पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुलहक़ स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाइपास, खेमनीचक और जीरो माइल होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जाना है जिसकी कुल लंबाई 14.57 किमी है। इस परियोजना के संचालन के उपरांत सार्वजनिक वाहनों के परिचालन, यातायात बोझ और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण में कमी आने की संभावना है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन :**

  - **पटना स्मार्ट सिटी :** पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फ्लाइओवर के किनारे वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत गांधी मैदान के इन्ट्री प्वांइन्ट से दीघा गोलंबर तक कुल 7 किमी में गंगा पथ के उत्तर की ओर सौंदर्यीकरण/पुनर्विकास कार्य प्रस्तावित है। साथ ही, शहर को साफ-सुथरा और प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए कुल 25 ई-बसें चल रही हैं। वहीं, 20 सरकारी भवनों/ स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि 908 किलोवाट आवर पीक बिजली प्राप्त की जा सके।

  - **बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत 37 भवन-स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि 320 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।

  - **भागलपुर स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत 7 भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि 336 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।

  - **मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत एक भवन/ स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है ताकि 25 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।

- **नगर विकास भवन निर्माण योजना :** इस योजना के तहत वर्षाजल संग्रहण/ सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है। साथ ही, भवन परिसरों में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाने हैं।

17. जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वृहत और मध्यम योजनाओं के तहत सिंचाई के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2023-24 में वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए खरीफ, रबी और गरमा मौसमों में कुल 25.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम में 22.00 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य था लेकिन 19.75 लाख हे. क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है।

- **हर खेत तक सिंचाई का पानी (सात निश्चय-2) :** राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के तहत ''हर खेत को सिंचाई का पानी'' उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में असिंचित खेतों को सिंचाई प्रदान करना है। क्षेत्र सर्वेक्षण और किसानों से परामर्श के बाद उपयुक्त योजनाओं की पहचान की गई हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 में जल संसाधन विभाग द्वारा 1165 योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिनमें से 619 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 546 में काम प्रगति पर है।

- **गंगाजल आपूर्ति योजना :** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षो की प्रकृति में परिवर्तन और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण दक्षिण बिहार के कई ईलाकों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। प्रभावों को सीमित करने और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत गंगाजल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा जैसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति से इन शहरों में भू-जल का दोहन कम हो जायेगा, परिणामस्वरूप भू-जल के स्तर में वृद्धि होगी। यह योजना राज्य में अपने किस्म की पहली योजना है जिसके लिए बरसात के मौसम में गंगा से अधिशेष पानी को लिफ्ट कर राजगीर और तेतर जलाशयों में भंडारित किया जाएगा, इससे इन क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज हो सकेगा। आम जनों के पेयजल के साथ जू-सफारी तथा नेचर सफारी को भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।

- **फल्गू नदी पर ''गया जी डैम'' (रबर डैम) :** विष्णुपद मंदिर के समीप फल्गू नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा देश के सबसे लंबे रबर डैम 'गया जी डैम' का निर्माण किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इस योजना पर 386.85 करोड़ रु. व्यय हुए हैं और इससे मंदिर के सामने 500 मीटर विस्तार में कम से कम 2 फीट गहरा पानी सालो भर उपलब्ध रहेगा। रुड़की आइआइटी के पर्यवेक्षण में राज्य में बना अपने किस्म का पहला डैम 2022 में बनकर तैयार हुआ। योजना धार्मिक कृत्य करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाभप्रद है। इसके साथ-साथ मंदिर से सीता कुंड जाने के लिए फल्गू नदी पर सीता पुल भी बनाया गया है जिससे हजारों पर्यटक रोज वहां जाते हैं।

- **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना :** पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों की गाद हटाने और तटबंधों तथा बचे हुए ढांचों के कार्य किये जा रहे हैं। अभी इस परियोजना से 18,461 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है और मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 70,777 हेक्टेयर ह्रासित क्षमता पुन:स्थापित हुई है। योजना का लक्ष्य 64,240 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाना और 1,41,025 हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित करना है जिससे मधुबनी जिले के 19 प्रखंडों और दरभंगा जिले के 5 प्रखंडों को लाभ होगा।

- **सिंधवरणी जलाशय योजना :** मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड में यह योजना 125.82 करोड़ रु. के व्यय से पूरी की जा रही है। इससे 1660 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। खड़गपुर, तेतिया बांबर, और संग्रामपुर प्रखंडों के किसान इससे खास तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं, 145.43 करोड़ रु. के व्यय से पूरी होने वाली डकरा नाला पंप नहर योजना से 3284 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी जिससे सूर्यगढ़ा, मुंगेर सदर, जमालपुर और धनहरा प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे।

- **कुंडघाट जलाशय योजना :** 185.21 करोड़ रु. के व्यय से कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के बहुआर नदी के समीपवर्ती सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। योजना के तहत 300 मीटर लंबा मिट्टी का बांध, गेट-युक्त चहका (स्पिलवे) और वितरण प्रणाली का निर्माण होगा जिससे 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना का लक्ष्य हरित आच्छादन बढ़ाना और क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध कराना है।

- **सारण मुख्य नहर की पुनःस्थापना :** 333.49 करोड़ रु. के व्यय से 0.00 किमी से 17.00 किमी तक सारण मुख्य नहर का पुनःस्थापन कार्य किया जा रहा है। वहीं 235.24 करोड़ रु. के व्यय से औरंगाबाद जिले में 0.00 किमी से 10.20 किमी तक पूर्वी लिंक नहर का पुनःस्थापन और लाइनिंग का काम किया जा रहा है।

- **नदी जोड़ योजनाएं :** राज्य में मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की कई योजनाएं बनाई गई हैं।

  - **बागमती-बूढ़ी गंडक (बेलवा धार) नदी जोड़ योजना :** 130.88 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में किया जा रहा है।

  - **बागमती-बूढ़ी गंडक (शांति धार) नदी जोड़ योजना :** 120.96 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन समस्तीपुर जिले में किया जा रहा है।

  - **गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडक-माही-गंगा नदी जोड़ योजना :** 69.89 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों में किया जा रहा है। इन नदी अंतर्संबंधन योजनाओं के जरिए राज्य में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा के विकास और भूजल संभरण की योजना है।

18. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

- **प्रचार के प्रयास :** विभाग होर्डिंग, समाचारपत्रों में विज्ञान, नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के जरिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने में सक्रियता से लगा है। इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सूचनाओं के सतत प्रसार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके इसे जन अभियान बनाना है।

अनुसूची 1: विभागवार हरित बजट विवरण

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024.25

(राशि लाख रु. में)

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2023–24 हरित बजट पुन. अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
1	19–2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	151.19	0.01	0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पौधों का सम्पोषण कार्य किया जाएगा।	सतत भूमि उपयोग और योजना जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	19–2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	712.43	0.00	0.00	0.00		
3	19–2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	101.04	0.00	0.00	0.00		
4	19–2406011010112 प्राकृतिक वनों का विकास	2084.89	9989.97	10000.00	10000.00	अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण तथा मृदा जल संरक्षण कार्य किया जाएगा।	
5	19–2406017890105 प्राकृतिक वनों का विकास	1800.00	0.00	0.00	0.00		
6	19–2406017960135 प्राकृतिक वनों का विकास	518.00	0.00	0.00	0.00		
7	19–2406018000101 नहर तट फार्म	0.00	0.01	0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पौधों का सम्पोषण कार्य किया जाएगा।	
8	19–2406017890102 नहर तट फार्म	423.03	0.00	0.00	0.00		
9	19–2406018000105 पथ तट फार्म	345.61	0.01	0.00	0.00	राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम–निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/ अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली संड़क पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशाला स्थापित करना तथा उनके द्वारा रैयति भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15
10	19–2406017890103 पथ तट फार्म	415.75	0.00	0.00	0.00		
11	19–2406011020109 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी	3676.32	10000.00	10000.00	10000.00	अधिसूचित वनभूमि पर बाहर पथ, नहर, नदी तट किनारे वृक्षारोपण, शहरी वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण कार्य किया जाएगा।	..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
12	19–2406017890106 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी	1639.64	0.00	0.00	0.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2023–24 हरित बजट पुन. अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
14	19–2406021120101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	5621.14	10000.00	10000.00	10000.00	इको पर्यटन एवं पार्क विकास कार्य अन्तर्गत नये पार्कों का विकास एवं रख–रखाव कार्य किया जाएगा।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
15	19–2406027890102 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	1614.29	0.00	0.00	0.00		
16	19–2406011050104 प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	773.22	1000.00	1000.00	1000.00	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अनुदान की राशि से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे। इस योजना से सभी जिलों में प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।	वायु और जल प्रदू''ाण उपशमन स्वच्छता और अपशि''ट प्रबंधन ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन विनियमन एवं प्रवर्तन
17	19–4406010700102 भवन	2420.27	3500.00	3586.98	3586.98	अधिसूचित वनभूमि के अंदर वनागार, विश्रामागार, कार्यालय तथा आवास का निर्माण कार्य कराया जाएगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 15 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
18	19–4406010700101 सड़क और पुल	63.24	500.00	500.00	500.00	राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों का मरम्मती कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
19	19–2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	924.26	1000.00	1000.00	1000.00	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं संर्वद्धन कार्य।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
20	19–2406011050105 प्लांट टिशू कल्चर लैब	0.00	200.00	200.00	200.00	प्लांट टिशु कल्चर लैब की स्थापना एवं विकाास कार्य किये जाएंगे। जिससे अच्छी गुणवत्ता के पौधे का उपयोग वृक्षरोपण कार्य में किया जाएगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुसंधान एवं विकास

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
21	19–2406021100324 बाघ परियोजना	199.55	151.64	0.00	0.00	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों के संरक्षण एवं उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
22	19–2406021100326 गज परियोजना	10.47	3.78	0.00	0.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किया जाएगा।	
23	19–2406021100323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास	0.00	744.00	250.00	250.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	
24	19–2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	0.00	30.00	30.00	इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 14 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
25	19–2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	95.23	407.90	214.80	214.80	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढाँचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
26	19–2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	5.07	0.00	25.00	25.00	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
27	19–2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम		0.00	233.00	233.00	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
28	19–2406021100224 बाघ परियोजना	238.01	151.64	0.00	0.00	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं उनके अधिवास के संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
29	19–2406021100226 गज परियोजना	15.70	5.66	0.00	0.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किए जाएंगे।	
30	19–2406021100223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास मिशन	0.00	2233.00	1554.70	1554.70	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	
31	19–2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना			550.00	550.00	इस योजनान्तर्गत जलीय पौधों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाए किये जाते हैं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 14 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
32	19–2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	39.62	1224.00	817.00	817.00	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढाँचागत सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
33	19–2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00		37.50	37.50	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
34	19–2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम			350.00	350.00	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
35	19–2406010010001 निदेशन और प्रशासन	1903.31	2321.81	2692.24	2692.24	मुख्यालय सहित 15 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्युत, अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
36	19–2406010030001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु	711.23	701.26	691.80	691.80	इस उपशीर्ष से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है एवं राज्य वन प्रशिक्षण केन्द्र, गया में वनरक्षी, वनपाल के प्रशिक्षण कार्य पर व्यय किया जाता है तथा 2 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेनतादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
37	19–2406010700001 सडक एवं पुल	395.33	400.00	480.00	480.00	2030 कि0मी0 वन पथ का रख–रखाव पर व्यय किया जाता है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
38	19–2406010700002 भवन	413.93	420.00	480.00	480.00	786 विभागीय भवन का रख–रखाव पर व्यय किया जाता है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 9 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
39	19–2406011010001 वनों का विस्तार उन्नति एवं सुरक्षा	13610.71	17339.49	18862.51	18862.51	इस उपशीर्ष में बिहार से 27 वन प्रमण्डलों के स्थायी पौधशाला एवं उसके रख रखाव पर व्यय तथा कार्यालयों के स्थायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संवदिा पर नियोजित कर्मी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्यंत अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
40	19–2406011010002 वर्किंग प्लान प्रमण्डल	113.71	155.47	135.34	135.34	इस उपशीर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रत्येक वन प्रमण्डल हेतु दस वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने संबंधित कार्यों पर व्यय किया जाता है एवं स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
41	19–2406021100003 अभयारण्य	1007.71	1385.45	1454.01	1454.01	इस उपशीर्ष में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल–1 एवं 2 के बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्य एवं कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संविदा पर नियोजित कर्मी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
42	19–2406021110001 अन्य उद्यान	1954.78	2909.87	4495.68	4495.68	इस उपशीर्ष में संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के 153 एकड़ में फेले उद्यान में केना गार्डन, मैंगो गार्डन, गुलाव गार्डन, औषधी गार्डन, फर्न गार्डन, और्किड घर, रोड के किनारे हेज तथा दो बड़े दूब घास गार्डन का रख रखाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त टिकट खिड़की, ट्रेन का परिचालन, ट्रेन ट्रैक का रख–रखाव, शिशु उद्यान का रख–रखाव, मछली घर का रख–रखाव, जल उद्यान के रख रखाव के साथ–साथ पूरे उद्यान में घास की कटाई एवं प्रतिदिन साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। उद्यान के अंदर अवस्थित 45 केजों में 600 जानवरों का आहार, चारा पहुंचाना एवं केज की सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। उद्यान में सॉन्दर्यीकरण हेतु मौसमी एवं वार्षिक फलों के पौधों का आवश्यकतानुसार रोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजगीर जू सफारी में भी जेंगली जानवर सिंह (Lion) आदि आ गये हैं। इसके साथ–साथ उद्यान की सुरक्षा का कार्य भी किया जाता है एवं राजगीर जू सफारी, नालंदा के जानवरों के आहार आदि पर व्यय तथा दोनों कार्यालयों में स्थायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि तथा संविदा पर रखे गए वन्यप्राणी रेस्क्यू टीम तथा कम्प्युटर ऑपरेटर एवं वाहन चालक के वेतन भुगतान किया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
43	19–3435041030001 बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण	74.78	81.00	85.50	85.50	इस उपशीर्ष से विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का पर्यावरण स्वीकृति यथा भवन निर्माण, खनन कार्य आदि तथा बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि भुगतान किया जाता है।	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 एस डी जी 9 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
44	19–3435031020001 बिहार राज्य जैव विविधिता पर्षद्	151.09	467.03	471.60	471.60	इस उप शीर्ष में Biodiversity Act के तहत गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियां (Biodiversity Management Committee) एवं जैव विविधिता पंजी (Public Biodiversity Register) का निर्माण कराना है एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
45	19–2406021100329 बाघ परियोजना एवं गज	0.00	0.00	200.00	200.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
46	19–2406021100328 बाघ परियोजना एवं गज	0.00	215.66	50.00	50.00		
47	19–2406041010303 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	33.20	33.20	ग्रामीण किसानों को वनरोपण के लिए प्रोत्साहित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
48	19–2406021100229 बाघ परियोजना एवं गज	0.00	0.00	600.00	600.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
49	19–2406021100228 बाघ परियोजना एवं गज	0.00	954.69	500.00	500.00		
50	19–2406041010203 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	49.80	49.80	ग्रामीण किसानों को वनरोपण के लिए प्रोत्साहित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
51	19–2406010030006 वाणिकी महाविद्यालय मुंगेर	0.00	1850.20	2610.56	2610.56	शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 4 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
52	19–3451000900006 पर्यावरण एवं वन विभाग	574.23	851.05	1061.55	1061.55	मुख्यालय का वेतन इत्यादि।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
	योगफल	**51875.46**	**81164.60**	**85302.79**	**85302.79**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग						
1	36.4215011020103 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	1709.55	4200.00	3338.00	3338.00	कुँओं का जिर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	36–4215017890111 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	353.32	800.00	1662.00	1662.00		
3	36–4215017960107 जलापूर्त्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिवयय	36.63	0.00	0.00	0.00		
	योगफल	**2099.50**	**5000.00**	**5000.00**	**5000.00**		
	ऊर्जा विभाग						
1	10–6801002010101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम (पनबिजली उत्पादन)	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	पनबिजली परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा कार्बन क्रेडिट में वृद्धि होगी, प्रदूषण में कमी आयेगी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन 'ामन और अनुकूलन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 7 एस डी जी 9 एस डी जी 12 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास
2	10–2810001040101 अपरंपरागत उर्जा श्रोत	4250.00	5000.00	10000.00	10000.00	ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रीड पर ऊर्जा की निर्भरता को कम किया जा सकेगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित R.P.O लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगा।	
3	10–4810001900102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 की परियोजना	0.00	0.00	15000.00	15000.00	कजरा (लखीसराय) में सौर ऊर्जा एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का अधिष्ठापन पर्यावरण के अनुकूल होगा, जल–जीवन–हरियाली अभियान का भी संवर्द्धन करेगा, इसके अतिरिक्त राज्यों के लिए निर्धारित नवीकरणीय क्रय दायित्व के साथ–साथ ऊर्जा भंडारण को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा तथा राज्य के औधोगिकरण में भी सहायक होगा।	
	योगफल	**4250.00**	**7000.00**	**27000.00**	**27000.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
	स्वास्थ्य विभाग						
1	20–4210011100118 जल–जीवन–हरियाली	76.69	500.00	350.00	350.00	वर्षा जल संचयन एवं हरित संरचना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
	योगफल	**76.69**	**500.00**	**350.00**	**350.00**		
	ग्रामीण विकास विभाग						
1	42–2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना–2	0.00	0.00	4000.00	4000.00	स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के द्वितीय चरण अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव का संकल्प लिया गया है। इसके तहत खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) का स्थायित्वय बनाये रखते हुए चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाना लक्षित है।	स्वच्छता और अपशि"ट प्रबंधन वायु और जल प्रदू"ाण उपशमन ..... एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	42–2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	63754.45	117156.00	70495.00	70495.00		
3	42–2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	33366.52	37700.00	23400.00	23400.00		
4	42–2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	16239.82	30040.00	18075.00	18075.00		
5	42–2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	9899.28	9650.00	6000.00	6000.00		
6	42–2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	908.86	3004.00	1808.00	1808.00		
7	42–2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	605.91	950.00	600.00	600.00		
8	42–2515000010110 जल जीवन हरियाली मिशन	170.00	1071.00	1000.00	1000.00	जल–जीवन–हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अनुश्रवण करने के लिए मिशन का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत जल–जीवन–हरयिाली अभियान से लोगों को जागरूक करना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
9	42–2220601010101 जल जीवन हरियाली जागरूकता	0.00	100.00	79.00	79.00		
	योगफल	**124944.84**	**199671.00**	**125457.00**	**125457.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
परिवहन विभाग							
1	47–3055001900104 बिहार स्वच्छ ईधन योजना	16.40	2500.00	1500.00	1500.00	वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु डीजल/पेट्रूल चालित वाहनों को सी0एन0जी0 में सम्परिवर्तन हेतु सब्सिडी।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा वायु और जल प्रदू'ाण उपशमन ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**16.40**	**2500.00**	**1500.00**	**1500.00**		
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50–4702001010106 हर खेत तक सिंचाई का पानी	11011.62	28220.00	28560.00	28560.00	जल संरक्षण/भू–जल पुनर्भरण मृदा अपरदन से सुरक्षा । सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पइन/तालाब बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	50–4702007890106 हर खेत तक सिंचाई का पानी	1788.73	5440.00	5440.00	5440.00		
3	50–4702007960107 हर खेत तक सिंचाई का पानी	53.43	340.00	0.00	0.00		
4	50–4702001020102 सतही जल योजना	2457.38	1660.00	840.00	840.00		
5	50–4702007890104 सतही जल योजना	389.76	320.00	160.00	160.00		
6	50–4702007960105 सतही जल योजना	17.93	20.00	0.00	0.00		
7	50–4702001020107 जल जीवन हरियाली	24157.98	23240.00	24360.00	24360.00		
8	50–4702007890105 जल जीवन हरियाली	3969.52	4480.00	4640.00	4640.00		
9	50–4702007960106 जल जीवन हरियाली	135.97	280.00	0.00	0.00		
10	50–4702001010205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	730.89	8300.00	8400.00	8400.00		
11	50–4702007890205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	137.96	1600.00	1600.00	1600.00		
12	50–4702007960206 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	8.62	100.00	0.00	0.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
लघु जल संसाधन विभाग							
13	50–4702001010305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	477.46	2766.39	2100.00	2100.00	जल संरक्षण/भू–जल पुनर्भरण मृदा अपरदन से सुरक्षा। सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पइन/तालाब बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
14	50–4702007890305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	91.97	533.28	400.00	400.00		
15	50–4702007960306 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	7.23	33.33				
16	50–4702001010101 सतही जल योजना	510.39	1245.00	1680.00	1680.00		
17	50–4702007890101 सतही जल योजना	75.96	240.00	320.00	320.00		
	योगफल	**46022.80**	**78818.00**	**78500.00**	**78500.00**		
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48–2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना (SBM)	858.00	48198.00	0.00		इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग हरित बजट के अन्तर्गत रखा जा सकता है।	स्वच्छता और अपशि"ट प्रबंधन वायु और जल प्रदू"ाण उपशमन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	48–2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना (SBM)	572.00	10000.00	0.00			
3	48–2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	0.00	412100.00	1000.00	1000.00		
4	48–2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	0.00	199.97	1000.00	1000.00		
5	48–2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	0.00	100.00	1000.00	1000.00		
6	48–2217030510212 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	1516.00	1516.00		
7	48–2217030510309 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	1500.00	1500.00		
8	48–2217030510213 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	13644.00	13644.00		
9	48–2217030510310 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	9000.00	9000.00		
10	48–2217030510214 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	26660.00	26660.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
11	48–2217030510311 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	10000.00	10000.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग हरित बजट के अन्तर्गत रखा जा सकता है।	स्वच्छता और अपशि''ट प्रबंधन वायु और जल प्रदू''ाण उपशमन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
12	48–2217030510215 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	4246.00	4246.00		
13	48–2217030510312 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	1000.00	1000.00		
14	48–2217030510216 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	2132.00	2132.00		
15	48–2217030510313 स्वच्छ भारत मिशन–2.0	0.00	0.00	1000.00	1000.00		
	योगफल	**1430.00**	**470597.97**	**73698.00**	**73698.00**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03–2059800530013 आवासीय/गैर–आवासीय उद्यानों/पार्कों का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार	602.66	1000.00	1000.00	1000.00	कार्बन उत्सर्जन स्तर एवं प्रदूषण स्तर को बनाए रखने हेतु पार्कों का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	03–4406010510101 वाणिकी महाविद्यालय	3452.56	0.00	0.00	0.00	हरित पट्टी के विस्तार आदि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन स्तर एवं प्रदूषण स्तर को बनाए रखना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 15 ..... प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
3	03–4406010510102 डॉल्फिन रिसर्च सेंटर	177.45	1548.49	0.00	0.00	डॉल्फिन का संरक्षण एवं उसकी प्रजाति को बढ़ाबा देना।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 15 ..... प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास
	योगफल	**4232.67**	**2548.49**	**1000.00**	**1000.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
कृषि विभाग							
1	01–2401001090122 फसल कृषि कर्म	8300.00	2358.00	2356.80	2356.80	सिंचाई हेतु हर खेत तक पानी की उपब्धता सुनिश्चित करना।	सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	01–2401007890152 फसल कृषि कर्म	1600.00	600.00	600.00	600.00		
3	01–2401007960174 फसल कृषि कर्म	85.26	42.00	43.20	43.20		
	योगफल	**9985.26**	**3000.00**	**3000.00**	**3000.00**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन							
1	02–2404000030101 प्रशिक्षण	251.62	340.00			प्रशिक्षण पर व्यय।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
	योगफल	**251.62**	**340.00**	**0.00**	**0.00**		
गन्ना उद्योग विभाग							
1	45–2401001080109 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	1377.60	3320.00	3109.52	3109.52	वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 2500 लाख रू0 की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देय गन्ना के उत्पादन उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 3760 लाख रू0 की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। कुल 2500 लाख रू0 में से 2024.42 लाख रू0 का व्यय तृस्तरीय बीज उत्पादन मद, अन्तवर्ती खेती मद एवं बडचिप विधि मद में किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा उक्त योजनान्तर्गत कम जल की आवश्यकता वाले गन्ना प्रभेद Cop-9301, CO-98014 एवं CoLK-94184 चयनित है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुसंधान एवं विकास
2	45–2401007890108 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	56.30	640.00	601.60	601.60		
3	45–2401007960129 ईंख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	10.93	40.00	48.88	48.88		
4	45–2852082010103 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	4980.00				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 ..... अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
5	45–2852087890101 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	960.00				
6	45–2852087960102 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	60.00				
	योगफल	**1444.83**	**10000.00**	**3760.00**	**3760.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पंचायती राज विभाग							
1	16–2515001960009 15वें वित्त आयोग (Tied)	34578.00	34956.00	37026.00	37026.00	Tied Grant का 100 प्रतिशत राशि का व्यय स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त, वर्षा जल संचयन, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सिंचाई क्षतमा वृद्धि हेतु चैक डेम/आहर, पईन का निर्माण एवं एक से तीन हेक्टेयर के जल संग्रहण क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आदि कार्य किया जाना है। जिससे पर्यावरण को स्वच्छ एवं रोगमुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन निवेश
2	16–2515001970006 15वें वित्त आयोग (Tied)	34659.32	34964.72	37026.00	37026.00		
3	16–2515001980016 15वें वित्त आयोग (Tied)	161400.04	163128.00	172788.00	172788.00		
	योगफल	**230637.36**	**233048.72**	**246840.00**	**246840.00**		
	100 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान	**477267.43**	**1094188.78**	**651407.79**	**651407.79**		
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48–2215011910106 जल–जीवन–हरियाली अभियान	180.00	3330.00	300.00	270.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में तालाब, पोखर एवं कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को संतुलित रखने एवं भू–गर्भ जल स्रोत को संरक्षित करने में सहायक है। कुल बजट राशि का लगभग 90 प्रतिशत भाग हरित बजट के अन्तर्गत रखा जा सकता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	48–2215011920103 जल–जीवन–हरियाली अभियान	274.50	1980.00	300.00	270.00		
3	48–2215011930102 जल–जीवन–हरियाली अभियान	346.50	1080.00	300.00	270.00		
4	48–2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	1377.03	1600.00	1944.00	1555.20	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर टू डोर कचड़ा उठाव का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत भाग हरित बजट के अन्तगत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन ..... एस डी जी 6 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन
5	48–2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	48.00	400.00	440.00	352.00		
6	48–2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	400.00	616.00	492.00		
	योगफल	**2226.03**	**8495.88**	**3900.00**	**3209.20**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)							
कृषि विभाग							
1	01–2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना	85.48	0.00	982.24	845.00	जैविक विधि से खेती एवं जैविक प्रमाणिकता हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना तथा जैविक उपादान को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	01–2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	56.99	0.00	228.23	196.00		
3	01–2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	10.30	0.00	58.12	50.00		
4	01–2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.00	4.15	3.73		
5	01–2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	0.52	403.75	126.39	95.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने संबंधित कार्य घटकों का कार्यान्वयन।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
6	01–2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	4652.00	1469.00	2278.30	1709.00	पक्का चेक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेंच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
7	01–2401007890241 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती	15.43	0.00	249.88	215.00	सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली (PGS-Particepatory Guarantee System) पद्धति के तहत जैविक खेती।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
8	01–2401007960263 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती	0.00	0.00	17.88	15.00		
9	01–2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	176.54	0.00	7025.93	5269.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने संबंधित कार्य घटकों का कार्यान्वयन।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
10	01–2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	136.64	3484.02	1532.64	1149.00		
11	01–2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	47.81	1838.52	491.57	369.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)							
कृषि विभाग							
12	01–2402007890302 मृदा तथा जल संरक्षण	897.00	0.00	577.76	433.00	पक्का चेक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जिर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैचुगार्ड ट्रेंच एवं पौधा रोपन आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
13	01–2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन		0.00				
14	01–2402007960309 मृदा तथा जल संरक्षण		0.00	41.44	31.00		
15	01–2401007960358 मृदा तथा जल संरक्षण		0.00	1.25	1.00		
16	01–2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)		0.00	1686.43	1265.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने संबंधित कार्य घटकों का कार्यान्वयन।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
17	01–2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)		0.00	29.41	22.00		
	योगफल	**6078.71**	**7195.29**	**15331.62**	**11667.73**		
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50–4702001010101 लघु सिंचाई	510.39	933.75			जल संरक्षण/भू–जल पुनर्भरण मृदा अपरदन से सुरक्षा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	50–4702007890101 लघु सिंचाई	75.96	180.00				
3	50–4702007960103 लघु सिंचाई	3.11	11.25				
	योगफल	**589.46**	**1125.00**	**0.00**	**0.00**		
	75 से 90 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान	**8894.20**	**16816.17**	**19231.62**	**14876.93**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)							
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42–2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	89531.23	223343.25	371241.00	241306.65	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ–साथ टिकाउ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य तालाब, आहर, खेत–पोखर एवं पइन इत्यादि जल संचयन संरचनाओं का जीर्नोद्धार किया जाताा है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 8 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	42–2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	12470.25	62250.00	70000.00	45500.00		
3	42–2501061010207 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	98.00	73.50	महिला सशक्तिकरण योजना को राष्ट्रीय किसान नीति के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, विशेष रूप किसान महिलाओं के लिए। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत वित्त पोषित करती है। एम0के0एस0पी0 योजना का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि में स्वयं रोजगार के अवसर सथापित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 5 एस डी जी 8 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
4	42–2501061010307 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	66.00	49.50		
5	42–2501067890206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	20.00	15.00		
6	42–2501067890306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	12.00	9.00		
7	42–2501067960206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	2.00	1.50		
8	42.2501067960306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एम0के0एस0पी0 (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	2.00	1.50		
	योगफल	**102001.48**	**285593.25**	**441441.00**	**286956.65**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
1	01–2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	143.41		259.74	130.00	फसल प्रत्यक्षण, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	01–2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	5939.00	6801.42	5499.20	3849.00	जैविक फसलों/सब्जी फसलों का उत्पादन।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
3	01–2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	1002.32	1709.73	1400.00	980.00		
4	01–2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	53.74	109.00	100.80	71.00		
5	01–2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	140.56	0.00	295.01	186.00	वर्षा आधारित 17 जिलों में फसल, उद्यान एवं पशुधन आधारित कृषि प्रणाली अपनाने हेतु आवश्यक शष्य क्रियाएं।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
6	01–2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	19.29	0.00	74.63	47.00		
7	01–2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1.07	0.00	5.36	3.00		
8	01–2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	0.00				
9	01–2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	14.28	0.00	17.37	11.00		
10	01–2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.84	0.00				
11	01–2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)		0.00			समेकित कृषि प्रणाली	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
12	01–2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1805.99	3882.26				
13	01–2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)		0.00				
14	01–2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	0.23	75.48				

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
15	01–2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	2672.00	3301.00	4713.60	3300.00	पक्का चेक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैचुगार्ड ट्रेंच एवं पौधा रोपन आदि। वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जलछाजन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य कर भू–क्षरण को रोकते हुए भूमि संरक्षण तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
16	01–2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	515.00	840.00	1200.00	840.00		
17	01–2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	32.00	59.00	86.40	60.00		
18	01–2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	6513.00	4359.00	9806.76	6865.00	पक्का चेक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जिर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैचुगार्ड ट्रेंच एवं पौधा रोपन आदि।	
19	01–2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	1256.00	1109.00	2482.24	1738.00		
20	01–2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	78.00	78.00	178.28	125.00		
21	01–2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)		0.00				
22	01–2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	56.00	26.00				
23	01–2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	553.33	982.35	691.99	346.00	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, ड्रीप सिंचाई	सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
24	01–2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	106.66	250.00	175.29	88.00		
25	01–2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	6.66	17.50				
26	01–2401001190224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	830.00	2358.00	2979.63	1490.00		
27	01–2401007890235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	160.00	600.00	753.71	377.00		
28	01–2401007960257 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	10.00	42.00	54.16	27.00		
	योगफल	**21909.38**	**26599.73**	**30774.17**	**20533.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2023–24 हरित बजट पुन. अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)							
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02–2405001010104 तालाब मत्स्यपालन का विकास एवं जीर्णोद्धार	4819.28	5843.19	7242.19	5431.64	1. भु–जल स्तर में वृद्धि। 2. जल संरक्षण। 3. जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग। 4. पारिस्थितिकी संतुलन। 5. अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगठित मत्स्य पालन हेतु करना।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	02–2405001010117 मत्स्य सम्पदा– 7 निश्चय–2	4167.97	5620.88	7494.00	5620.50		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
3	02–2405007890102 मत्स्य सम्पदा– 7 निश्चय–2	842.11	1500.00	2000.00	1500.00		
4	02–2405007960110 मत्स्य सम्पदा– 7 निश्चय–2	42.86	379.13	506.00	379.50		
5	02–2405007890101 मुख्यमंत्री तालाब सांख्यिकी विकास मछुआरों की सहायता	0.00	2052.75	2563.00	1922.25		हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
6	02–2405007960109 मुख्यमंत्री तालाब सांख्यिकी विकास मछुआरों की सहायता	0.00	518.80	648.44	486.33		
	योगफल	**9872.22**	**15914.74**	**20453.63**	**15340.22**		
शिक्षा विभाग							
1	21–4202012010106 जल–जीवन–हरियाली	0.00	75.00	0.00		राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय अन्तर्गत चिन्हित विद्यालयों में वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण 80,000/–(अस्सी हजार रू०) मात्र प्रति विद्यालय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्य हेतु निर्माण कार्य की योजना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	21–4202012020115 जल–जीवन–हरियाली	0.00	375.00	0.00		एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत चिन्हित विद्यालयों में वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण 80,000/–(अस्सी हजार रू०) मात्र प्रति विद्यालय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्य हेतु निर्माण कार्य की योजना है।	
	योगफल	**0.00**	**450.00**				

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)							
परिवहन विभाग							
1	47–3055001900102 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	4000.00	11600.00	8700.00	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नये सी0एन0जी0 बसों के क्रय हेतु अनुदान।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा वायु और जल प्रदूषण उपशमन ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**0.00**	**4000.00**	**11600.00**	**8700.00**		
उद्योग विभाग							
1	23–2851001070101 रेशम विकास की योजना			400.00	274.00	क्षेत्रीय कीटपालकों द्वारा अंडी एवं आसन/अर्जुन के पौधों का वृक्षारोपण करना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाय एवं स्वरोजगार सृजित हो सके।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	23–2852801020160 औद्योगिक प्रोत्साहन नीति	0.00		49753.00	34080.80	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत इथेनॉल उत्पादन प्लांट्स की स्थापना में सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करना ताकि राज्य में जैविक ईंधन के विकल्प के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।	
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**50153.00**	**34354.80**		
पंचायती राज विभाग							
1	16–2515001980115 सात निश्चय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	12695.04	9521.00	सुशासन के कार्यक्रम – 2020–2025 के अन्तर्गत "आत्मनिर्भर बिहार" के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत "स्वच्छ गांव – समृद्ध गांव" निश्चय के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्यक्रम है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चयनित सूची में खेल–कूद का आयोजन स्थल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सार्वजनिक स्थलों के प्राथमिकता के आधार पर सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना है, जिनका पांच वर्ष तक रख–रखाव की जिम्मेवारी अधिष्ठापन किये जाने वाले एजेंसी की होगी।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	16–2515007890115 सात निश्चय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	14162.96	10622.00		
3	16–2515007960120 सात निश्चय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	742.00	556.00		
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**13437.04**	**10077.00**		
	50 से 75 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान	**133783.08**	**332557.72**	**567858.84**	**375961.67**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48–2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	1312.00	393.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नाला, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छत एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	48–2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	100.00	30.00		
3	48–2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	60.00	100.00	30.00		
4	48–2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एंव अन्य सैनिटेशन योजना	2574.06	5550.00	2000.00	600.00		
5	48–2215021070101 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	0.00	5277.59	15000.00	4500.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु योजना (नाला, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य) किया जाता है यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छता एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
6	48–2215027890103 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	0.00	4764.91	11500.00	3450.00		
7	48–2215027960105 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	0.00	637.50	3500.00	1050.00		
8	48–2217011910109 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	59.32	2250.00	500.00	150.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पार्क निर्माण, तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण का स्वच्छ एवं प्रदूषित रहित रखने में सहायक ह।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
9	48–2217011910116 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	79.50	900.00	500.00	150.00		
10	48–2217031920105 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	156.56	900.00	500.00	150.00		
11	48–2217031930104 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	69.53	750.00	500.00	150.00		
12	48–5075601900101 पटना मेट्रो रेल	47950.00	21500.00	5000.00	2500.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुगम एवं प्रदूषण रहित सुविधा होगी तथा यातायात पर दबाव कम होगा, जो शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 9 एस डी जी 11 एस डी जी 15 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2023–24 हरित बजट पुन. अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
13	48–2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण–सात निश्चय–2	0.00	0.00	0.01	0.00	इसके योजना के अंतर्गत शवदाह हेतु विद्युत/परम्परागत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना है, जिससे शवों को वैज्ञानिक तरीके से दाह संस्कार किया जायेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन ..... एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
14	48–2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण–सात निश्चय–2	0.00	4800.00	4999.99	1999.99		
15	48–5075600500101 पटना मेट्रो रेल		0.00	1000.00	500.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुगम एवं प्रदूषण रहित सुविधा होगी तथा यातायात पर दबाव कम होगा, जो शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 9 एस डी जी 11 एस डी जी 15 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
16	48–7075601900101 पटना मेट्रो रेल		0.00	2000.00	1000.00		
	योगफल	**50888.97**	**47510.00**	**48512.00**	**16652.99**		
कृषि विभाग							
1	01–2401001040106 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	2801.00	3966.04	9034.40	4065.00	जल, जीवन एवं हरियाली योजना/जलवायु परिवर्तन से संबंधित खेती का प्रोत्साहन।	सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	01–2401007890147 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	540.00	1009.19	2300.00	1035.00		
3	01–2401007960169 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	34.00	70.71	165.60	75.00		
4	01–2401001190101 उद्यान विकास योजना	6450.00	11012.00	23568.00	11784.00	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, नये सब्जी बीजों को प्रोत्साहन देना, सुगंधित पौधों का क्षेत्र विकास–मेन्था एवं लेमनग्रास, सहजन का बीज वितरण, मखाना का चौर में क्षेत्र विस्तार, रूफ टॉप गार्डेन	सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
5	01–2401007890130 उद्यान विकास योजना	1243.00	2804.00	6000.00	3000.00		
6	01–2401007960152 उद्यान विकास योजना	78.00	196.00	432.00	216.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
7	01–2401001020201 कृषि उन्नति योजना (तेल तिलहन + खाद्य एवं पोषण सुरक्षा)	1727.96	2987.00	3886.21	1943.00	इसका मुख्य उद्देश्य धान, गेहूँ, दलहन, जूट, गन्ना फसल तथा तेलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु सभी आवश्यक घटकों यथा बीज वितरण, प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण, इत्यादि उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना है।	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
8	01.2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	249.53	760.00	1071.26	536.00		
9	01–2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.01	53.00	71.92	36.00		
10	01–2401001020301 कृषि उन्नति योजना (तेल तिलहन + खाद्य एवं पोषण सुरक्षा)	850.66	1769.00	893.27	447.00		
11	01–2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन		450.00				
12	01–2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	6.67	32.00	16.72	8.00		
13	01–2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00		687.84	172.00	बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज (धान, अरहर, उड़द, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मूंग ढैंचा) उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
14	01–2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	788.50	0.00	2653.43	1194.00	भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संचरणन का निर्माण, पौधा रोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहिन किसानों के लिए कार्य{म एवं उत्पादन प्रणाली आदि स्प्रींकलर/टपकन सिंचाई की योजना	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
15	01–2401007960261 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9.50	0.00	48.26	22.00		
16	01–2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	525.39	0.00	616.44	277.00		
17	01–2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल	0.00	0.00	174.65	44.00	बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज (धान, अरहर, उड़द, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मूंग ढैंचा) उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
18	01–2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल	0.00	0.00	2.91	1.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
19	01–2401007890239 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	152.00	0.00	673.31	303.00	भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संचरणन का निर्माण, पौधा रोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहिन किसानों के लिए कार्य{म एवं उत्पादन प्रणाली आदि स्प्रींकलर/टपकन सिंचाई की योजना	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
20	01–2401007890339 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	101.28	0.00	156.69	71.00		
21	01–2401007960361 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.33	0.00	11.22	5.00		
22	01–2401007960357 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि योजना		0.00	12.94	6.00	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, ड्रीप सिंचाई इत्यादि।	सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
	योगफल	**15573.83**	**25108.94**	**52477.07**	**25240.00**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02–2405001010219 नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	2709.43	1191.40	5636.24	1690.87	1. भु–जल स्तर में वृद्धि। 2. जल संरक्षण। 3. जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग। 4. पारिस्थितिकी संतुलन। 5. अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगठित मत्स्य पालन हेतु करना।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
2	02–2405001010319 नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	697.19	676.53	1408.87	422.66		
3	02–2405007890201 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	88.00	318.00	1504.20	451.26		
4	02–2405007960201 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	32.00	80.60	380.56	114.17		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2023–24 हरित बजट पुन. अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
5	02–2405007890301 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	58.67	120.00	376.00	112.80	1. भु–जल स्तर में वृद्धि। 2. जल संरक्षण। 3. जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग। 4. पारिस्थितिकी संतुलन। 5. अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगठित मत्स्य पालन हेतु करना।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
6	02–2405007960301 रिपेयरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	21.36	30.33	95.13	28.54		
	योगफल	**3606.65**	**2416.86**	**9401.00**	**2820.30**		
उद्योग विभाग							
1	23–2851001070101 रेशम विकास योजना	121.00	218.75			क्षेत्रीय कीटपालकों द्वारा तसर एवं अंडी के पौधो का वृक्षारोपण करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना एवं स्वरोजगार सृजित करना।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
	योगफल	**121.00**	**218.75**				
पंचायती राज विभाग							
1	16–2515001960003 15वें वित्त आयोग (Untied)	0.00		24684.00	9873.60	15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत Untied Grant का 40 प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट, खेल के मैदान, उद्यानों, खुला जिम की व्यवस्था, सैरातों का विकास एवं शवदाह गृह/विद्युत शवदाह गृह के निर्माण में खर्च किये जाने का प्रावधान है। जिससे पर्यावरण को स्वच्छ एवं रोगमुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सतत भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 6 एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 15 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	16–2515001970001 15वें वित्त आयोग (Untied)	0.00		24684.00	9873.60		
3	16–2515001980001 15वें वित्त आयोग (Untied)	0.00		115192.00	46076.80		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
पंचायती राज विभाग							
4	16–2515001960007 पष्ठम राज्य वित्त आयोग	0.00		61805.25	30902.63	षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत समान निधि (50 प्रतिशत) राशि का व्यय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निपटान, तरल अपशिष्ट का निपटान, सार्वजनिक शौचालय, श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान क निर्माण तथा खेल के मैदानों का प्रबंधन आदि कार्यो। में राशि व्यय किये जाने की संभावना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 एस डी जी 15 ..... निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
5	16–2515001970004 पष्ठम राज्य वित्त आयोग	0.00		61805.25	30902.63		
6	16–2515001980009 पष्ठम राज्य वित्त आयोग	0.00		288424.50	144212.25		
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**313108.50**	**154085.85**		
	25 से 50 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान	**70190.45**	**75254.55**	**423498.57**	**198799.14**		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37–4515001030316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1815.95	19543.43	34372.00	7884.95	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टि का कचड़ा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 12 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**1815.95**	**19543.43**	**34372.00**	**7884.95**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48–2217011910115 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00		1000.00	100.00	इस योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 10 फीट से कम चौड़ाई की गलियों का निर्माण पेभर ब्लॉक से कराया जाता है, जो वाटर रिचार्ज के अनुकूल है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	48–2217031930103 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00		9500.00	950.00		
3	48–2217017890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	5.66	149.99	500.00	50.00		
4	48–2217037890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	110.92	450.00	1500.00	150.00		
5	48–2217037960101 शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	100.00	0.00			
6	48–2217030510202 अमृत (AMRUT)	286.00	5240.00	0.00		इस योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण, जलापूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 एस डी जी 12 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
7	48–2217030510302 अमृत (AMRUT)	0.00	800.00	0.00	0.00		
8	48–2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	490.00	900.00	10000.00	500.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सिरवेज निर्माण का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जता है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
9	48–2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	1000.00	500.00	6000.00	300.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
10	48–3475007960202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	8.75	0.00		इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
11	48–3475007960302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	3.47		0.00			
12	48–2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन	245.00	900.00	10000.00	500.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सिरवेज निर्माण का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जता है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा ..... एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
13	48–2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन	285.00	500.00	6000.00	300.00		
14	48–2217030510206 स्मार्ट सिटी मिशन	245.00	900.00	10000.00	500.00		
15	48–2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन	245.00	500.00	6000.00	300.00		
16	48–2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	900.00	10000.00	500.00		
17	48–2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	500.00	6000.00	300.00		
18	48–2217030510208 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	104800.00	10480.00	इस योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण, जलापूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 11 एस डी जी 12 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
19	48–2217030510308 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	21000.00	2100.00		
20	48–2217030510209 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	3400.00	340.00		
21	48–2217030510210 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	5000.00	500.00		
22	48–2217030510211 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	4000.00	400.00		
	योगफल	**2916.05**	**12348.74**	**214700.00**	**18270.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
कृषि विभाग							
1	01–2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	2857.00	2673.47	15240.98	3048.00	आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	01–2401007890117 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	551.00	542.67	3879.00	776.00		
3	01–2401007960140 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	34.00	37.95	279.35	56.00		
4	01–2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	415.67			बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज (धान, अरहर, उड़द, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मूंग ढैंचा) उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
5	01–2401007890249 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	105.81				
6	01–2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	7.56	12.51	3.00		
7	01–2401001030318 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	263.91	160.09	40.00		
8	01–2401007890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	67.00	40.35	10.00		
9	01–2401007960371 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	4.69	0.00			
10	01–2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	163.00	0.00		तेलहनी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना	जलवायु परिवर्तन ‘मन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
11	01–2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	42.00	0.00			
12	01–2401007960256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन		3.00	0.00			
13	01–2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.10	89.00	0.00			

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
कृषि विभाग							
14	01–2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	23.00	0.00		तेलहनी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 2 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
15	01–2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	2.00	0.00			
	योगफल	**3442.10**	**4440.72**	**19612.28**	**3933.00**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03–4059010510101 भवन	2744.16	1253.00	17950.00	3590.00	Fly Ash Brick का प्रयोग कर मृदा संरक्षण को बढ़ाबा दिया जा रहा है। साथ ही सभी निर्माणाधीन भवनों, Rain Water Harvesting, Tree Plantation, use of STP Treated water in Flush and gardening, Energy efficient Appliances, Solar Panel Over roof top इत्यादि का प्रावधान किया जा रहा है।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 6 एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 12 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	03–4216017000101 अन्य आवास	2744.16	3010.00	43000.00	8600.00		
3	03–4059800510110 न्यायिक भवन	0.00	0.00	25.00	5.00		
4	03–4216017000102 न्यायिक आवासीय भवन	0.00	0.00	25.00	5.00		
	योगफल	**5488.32**	**4263.00**	**61000.00**	**12200.00**		
जल संसाधन विभाग							
1	49–2705000010204 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	100.00	500.00	100.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	49–2705000010304 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	683.00	564.40	2823.00	564.00		
3	49–4700800510207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	812.60	1316.40	11842.00	2368.40		
4	49–4700800510309 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1333.80	681.00	500.00	100.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
जल संसाधन विभाग							
5	49–4700800050101 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	100.00	140.00	200.00	40.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
6	49–4700800510102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	9.88	60.00	100.00	20.00	यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	
7	49–4700800510104 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएँ	18600.00	8002.50	8000.00	2000.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
8	49–4700800510105 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	11586.25	25339.25	68000.00	17000.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	
9	49–4700807890102 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	6705.50	9748.50	36530.00	9132.50		
10	49–4700800510310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	0.00	1358.20	12068.00	2413.60	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
11	49–4711010510110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	840.00	1225.00	10650.00	1065.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है जो पर्यावरण संरक्षण में स्वभाविक रूप से लाभकारी होगा	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
12	49–4711017890104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	2330.00	2372.90	23350.00	2335.00		
13	49–4711017960101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	313.30	402.10	3800.00	380.00		
14	49–4711010510111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएं	600.00	300.00	2000.00	200.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य नहरों के बाँध एवं तटबंधों पर सड़क निर्माण करना है, जो पर्यावरण संरक्षण के सभी कार्यक्रमों के संचालन में सहायक होगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
जल संसाधन विभाग							
15	49–4711010510209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	7280.00	8008.00	88100.00	8810.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है जो पर्यावरण संरक्षण में स्वभाविक रूप से लाभकारी होगा	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सतत भूमि उपयोग और योजना ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
16	49–4711010510309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	516.60	2198.20	12600.00	1260.00		
17	49–4711010510212 सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	1650.00	1815.00	20000.00	2000.00		
18	49–4700807890103 हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	400.00	1000.00	4000.00	1000.00	यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
19	49–4700807960101 हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	25.00	125.00	500.00	125.00		
20	49–4700800510106 हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	2075.00	3875.00	15500.00	3875.00		
21	03–4059800510124 जल संसाधन विभाग के भवनो का निर्माण	0.00	0.00	2000.00	200.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत वाल्मीकीनगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं अतिथिगृह का निर्माण कार्य है जिसमें परिसर में वृक्षरोपण एवं हरित आवरण की वृद्धि किये जाने से पर्यावरण संरक्षण में स्वाभाविक रूप से लाभकारी होगा।	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 2 एस डी जी 6 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
22	49–4711010510102 जल निस्सरण से संबंधित कार्य	0.00	0.00	200.00	20.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है जो पर्यावरण संरक्षण में स्वाभाविक रूप से लाभकारी होगा।	
	योगफल	**55860.93**	**68631.45**	**323263.00**	**55008.50**		
परिवहन विभाग							
1	47–3055001990101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	421.68	45.00			वित्तीय वर्ष 2023–34 में संभावित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रत्याशा में अन्य वाहनों के अलावे इ0 रिक्शा खरीद पर भी अनुदान	जलवायु परिवर्तन 'ामन और अनुकूलन ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	47–3055007890101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	81.30	100.00				
3	47–3055007960101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	5.09	10.00				
	योगफल	**508.07**	**155.00**	**0.00**	**0.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
पर्यटन विभाग							
1	46–5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	1952.61	2699.40	16200.00	3524.72	पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना। साथ ही वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर राज्य में इको–टूरिज्म का विकास किया जाना।तालाब में जल आपूर्ति एवं संरक्षण प्रदान किया जाना। वैशाली जिलान्तर्गत विश्व शांति स्तूप के समीप अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति। राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों का पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण। राजगीर के घोड़ा–कटोरा में पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर के घोड़ा–कटोरा में पर्यटकीय संरचनाओं का विकास । गया जिलान्तर्गत गुरपा पर्वत पर पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। गया जिलान्तर्गत गुरपा पर्वत पर पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 6 एस डी जी 12 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
	योगफल	**1952.61**	**2699.40**	**16200.00**	**3524.72**		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42–2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			124634.00	13086.57	इस योजनान्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर निरंतर कार्य किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार 6..... एस डी जी 5 एस डी जी 8 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	42–2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			64087.00	6729.14		
3	42–2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			25918.00	2721.39		
4	42–2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			13327.00	1399.34		
5	42–2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			2448.00	257.04		
6	42–2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)			1259.00	132.20		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
ग्रामीण विकास विभाग							
7	42–2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.		0.00	1080.00	113.40	इस योजनान्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर निरंतर कार्य किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार 6..... एस डी जी 5 एस डी जी 8 ..... अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
8	42–2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.		0.00	120.00	12.60		
9	42–2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	4880.00	512.40		
10	42–2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	814.00	85.47		
11	42–2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	1016.00	106.68		
12	42–2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	170.00	17.85		
13	42–2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	104.00	10.92		
14	42–2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	16.00	1.68		
15	42–2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	3000.00	315.00		
16	42–2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	2500.00	262.50		
17	42–2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	0.00	2000.00	210.00		
	योगफल	**0.00**	**0.00**	**247373.00**	**25974.18**		
	5 से 25 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान	**71984.03**	**112081.73**	**916520.28**	**126795.35**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48–3475001080202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	206.25	0.00		इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। कुल बजट राशि 05 प्रतिशत भाग हरित बजट के अन्तर्गत रखा जा सकता है	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... शिक्षा एवं जागरूकता
2	48–3475001080302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	0.00	0.00			
3	48–3475007890202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	160.00	0.00			
4	48–3475007890302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	0.00	0.00			
5	48–3475007960202 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	0.00	8.75	0.00			
6	48–3475007960302 स्वर्ण जंयती शहरोन्मुखी योजना (NULM)		0.00	0.00			
	योगफल	**0.00**	**375.00**	**0.00**	**0.00**		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42–2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	5394.95	4193.49			इस योजनान्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर निरंतर कार्य किया जाता है।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 5 एस डी जी 6 एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	42–2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	2882.56	3135.70				
3	42–2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	5543.16	3042.30				
4	42–2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	2961.60	1082.85				
5	42–2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	2535.79	1391.75				

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)							
ग्रामीण विकास विभाग							
6	42–2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1356.63	495.40			इस योजनान्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर निरंतर कार्य किया जाता है।	स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपशमन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 5 एस डी जी 6 एस डी जी 8 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
7	42–2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	38.00	50.00				
8	42–2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	25.33	126.67				
9	42–2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	231.00				
10	42–2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	33.00				
11	42–2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	108.50				
12	42–2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	15.50				
13	42–2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	10.50				
14	42–2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	1.45				
15	42–2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	635.40				
16	42–2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	75.00				
17	42–2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एन.आर.एल.एम.	0.00	586.10				
	योगफल	**20738.02**	**15214.61**	**0.00**	**0.00**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)							
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37–3054041050001 सड़क और पुल	8964.60	16457.14	200000.00	6440.00	सड़क किनारे वृक्षारोपण	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 12 एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	37–4515001030113 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	137.14	476.31	40671.00	128.00		
3	37–4515007960109 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	36.34	45.71	1844.00	3.20		
4	37–4515007890104 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	160.21	1097.14	53026.00	300.16		
5	37–4515001030216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2643.87	2388.52	147900.00	171.95		
	योगफल	**11942.16**	**20464.83**	**443441.00**	**7043.31**		
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02–2405001090102 मत्स्य प्रसार	81.00	70.13	1434.54	71.72	मत्स्य कृषकों में जागरूकता।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार ..... एस डी जी 14 ..... शिक्षा एवं जागरूकता
	योगफल	**81.00**	**70.13**	**1434.54**	**71.72**		
पथ निर्माण विभाग							
1	41–5054033370508 सड़क	1024.02	3993.38	137900.00	973.72	विषयांकित सभी परियोजनाओं में अनिवार्य वन रोपण, जैव विविधता के संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन का प्रावधान है।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	41–5054033370102 वृहद पथ	91.75	715.54				
3	41–5054037890101 वृहद पथ		0.00				
4	41–5054031010103 नाबार्ड	0.00	924.21				
	योगफल	**1115.77**	**5633.13**	**137900.00**	**973.72**		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)							
शिक्षा विभाग							
1	21–2202010010105 शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षिक आयोजन एवं महोत्सव	25.00	15.00	500.00	25.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपन के प्रति जागरूक एवं संवेदनशीन बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 4 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	21–2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.30	100.00	0.00		प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित होते है।	
3	21–2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	35.79	75.00	0.00		किलकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लेट कम्प्यूटर एवं अन्य का सौर ऊर्जा से संचालन अनवावश्यक लाइट की बत्ती न जलाने हेतु प्रोत्साहित करना। लुप्त प्राण प्राणियों पर जैसे ऊल्लू, गौरैयां संरक्षण आदि पर जागृति हेतु पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।	
4	21–2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	36.00	99.60	0.00		माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित होते है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 7 एस डी जी 9 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
5	21–4202012010105 प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण	300.00	470.12	70001.00	2100.03	बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा ऐसी भवन के निर्माण का निर्देश है कि घर रोशनदान युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता हो। छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। दिवाल पर भी पर्यावरण जागरूकता का चित्रण किया जा रहा है।	
6	21–4202012020103 माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	600.00	3428.91	46801.00	1404.03		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)							
शिक्षा विभाग							
7	21–2202010010002 प्रोत्साहन हेतु सामाजिक उत्सव	0.00	0.50			प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपन के प्रति जागरूक एवं संवेदनशीन बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 4 एस डी जी 13 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
8	21–2202011090004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	0.00	0.25				
	योगफल	**997.09**	**4189.38**	**117302.00**	**3529.06**		
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग							
1	24–2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार योजना	411.00	410.00	8113.00	405.65	जल–जीवन हरियाली अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन ..... एस डी जी 13 एस डी जी 15 ..... शिक्षा एवं जागरूकता
	योगफल	**411.00**	**410.00**	**8113.00**	**405.65**		
भवन निर्माण विभाग							
1	03–2059800530001 अनुरक्षण एवं मरम्मत	1553.40	2098.29	42500.00	2125.00	भू–जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन कार्य	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ..... एस डी जी 9 ..... कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	03–2059800530004 अनुरक्षण एवं मरम्मत			7000.00	350.00		
	योगफल	**1553.40**	**2098.29**	**49500.00**	**2475.00**		
	5 प्रतिशत तक श्रेणी का कुल बजट योगदान	**36838.44**	**48455.36**	**757690.54**	**14498.46**		
	महायोग	**798957.63**	**1679354.30**	**3336207.64**	**1382339.34**		

6. संदर्भ सूची

ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिशिएंसी, एलायंस फॉर ऐन इनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, 2022. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021–22. https://stateenergyefficiencyindex.in/wp-content/uploads/2023/04/State-Energy-Efficiency-Index-2021-22-Report.pdf

क्लाइमेट ट्रांसपैरेंसी. 2022. जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022. https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2022.

सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/

एक्स्टीन, डेविड, वेरा कुंज़ेल, और लॉरा शैफर. 2021. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf.

भारतीय वन सर्वेक्षण. 2022. ''स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021''. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

बिहार सरकार. 2015. ''राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना''.

बिहार सरकार. 2023. ''बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23''. वित्त विभाग, बिहार सरकार.

बिहार सरकार. 2023. ''चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–28)''. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

बिहार सरकार. 2024. ''बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24''. वित्त विभाग, बिहार सरकार.

भारत सरकार. 2011. जनसंख्या गणना. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables

भारत सरकार. 2019. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडैप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क, 2019–20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf

भारत सरकार. 2021. नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTIyOF8xNjE1MTk2MzIyX21lZGlhcGhvdG85NTY0LnBkZg==

भारत सरकार. 2022. वार्षिक रिपोर्ट 2022. भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, भूविज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार. https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/ar2022.pdf

भारत सरकार. 2022. लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स–ऍट ए ग्लांस – अनंतिम अनुमान. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार. लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स–ऍट ए ग्लांस. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट (desagri.gov.in)

भारत सरकार. 2023. ''नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023''. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी). जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार. https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf.

भारत सरकार. 2023. ''नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023''. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf.

भारत सरकार. भारत की जनगणना. 2011. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. http://www.censusindia.gov.in/.

भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1707520

गुप्ता, पी के, जे जी पटेल, आर पी सिंह, आइ एम बहुगुणा, और राज कुमार. 2021. ''स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन वेटलैंड्स''. स्पेस अप्लीकेशनंस सेंटर, इसरो https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

आइएमडी. 2023. ''भारतीय मौसम विज्ञान विभाग''. https://mausam.imd.gov.in.

नेशनल वेटलैंड स्टेटिस्टिक्स. टाइपवाइज एस्टिमेट्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया. https://indianwetlands.in/wetlands-overview/national-wetlands-statistics/

नीति आयोग. 2019. ''एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019–20''. नीति आयोग, भारत सरकार.

नीति आयोग. 2019. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स https://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf

नीति आयोग. 2020. ''एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21 – परफॉमेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज''. नीति आयोग, भारत सरकार. https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/state-compare?goal=3&area=IND010&timePeriod=2020

नीति आयोग. 2022. ''इंडियन मॉडल ऑफ एसडीजी लोकलाइजेशन''. नीति आयोग, भारत सरकार.

नीति आयोग. 2022. स्टेट इनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स – राउंड 1. 2022 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRoundI-10-04-2022.pdf

नीति आयोग. 2023. ''ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी''. प्रोसीडिंग्स ऑफ ए जी20

इंटरनेशनल कंफ्रेंस, नई दिल्ली. नीति आयोग. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-12/REVISED_Report-on-G20-Conference-on-Green-Growth_FINAL-REVISED.pdf.

पांडेय, स्वीटी, नवीन कुमार विद्यार्थी, राजनाथ राम, और राकेश सरवाल. 2022. ''स्टेट इनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स : राउंड–1''. मुद्रणपूर्व. ओपन साइंस फ्रेमवर्क. https://doi.org/10.31219/osf.io/8ec6q.

स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन वेटलैंड्स. स्पेस अप्लीकेशनंस सेंटर, इसरो, अहमदाबाद, भारत. https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. भारत सरकार.

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया स्कोर 2020. https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

विश्व बैंक. 2021. ''क्लाइमेट रिस्क कंट्री प्रोफाइल – इंडिया''. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15503-WB_India%20Country%20Profile-WEB.pdf

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार